दैनिक
सच्चे दिन

वर्ष-06 | अंक-196 | प्रात:कालीन हिन्दी दैनिक | भोपाल, शनिवार 17 अक्टूबर 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपये

चंबल एक्सप्रेस-वे के आसपास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाओं पर हुई चर्चा

औद्योगिक विकास को गति देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए शासन की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि दीपावली से पहले चंबल संभाग स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने और नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना, मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल तथा सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



जनविश्वास अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्यमियों से किया संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने चंबल एक्सप्रेस-वे के आसपास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाओं पर भी उद्यमियों के साथ चर्चा की।

मुख्यमंत्री न दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनविश्वास अभियान अंतर्गत मुरैना जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में दिव्यांगजनों के उपचार, पुनर्वास एवं समग्र विकास के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया तथा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्र में संचालित न्यूरोलॉजिकल पुनर्वास कक्ष, बाल पुनर्वास कक्ष, शिशु एवं बाल चिकित्सा उपचार कक्ष तथा विद्युत चिकित्सा कक्ष सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया।

शर्मा के अंगदान से तीन लोगों को मिला जीवन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि श्रीमती बिलाश टांटी शर्मा (शिवानी) के एम्स, भोपाल में अंगदान से तीन लोगों को जीवन मिला है। नर्मदापुरम जिले में बनखेड़ी के ग्राम खापा खुर्द निवासी श्रीमती शर्मा सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड हुईं थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि असहनीय दु:ख की घड़ी में उनके परिजन ने अंगदान का निर्णय लेकर मानवता, संवेदनशीलता और परोपकार की ऐसी मिसाल पेश की जो सभी को प्रेरित करेगी।

त्विषा शर्मा केस

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्ली। पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भोपाल की



सत्र अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई, त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह आदेश त्विषा के पिता नवनीधि शर्मा की याचिका पर दिया।

जवाब दाखिल करने के लिए समय

शिकायतकर्ता नवनीधि शर्मा की ओर से मुकदमे को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में लंबित कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने प्रतिवादियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। इस आदेश से केस की सुनवाई के स्थान को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। नवनीधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुकदमे को भोपाल की सत्र अदालत से दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। याचिका में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंकाएं जताई गई हैं।

पति को सांप से डसवाने वाली रविता को सजा-ए-मौत

प्रेमी को भी फांसी, मेरठ कोर्ट ने 3 दिन में 4 दोषियों को मौत की सजा दी

मेरठ। पति की हत्या करके सांप से डसवाने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को वारदात के 547 दिन बाद मेरठ जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने रविता और अमरदीप का पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना। जज ने दोनों से पूछा- तुम दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया है। क्या सजा चाहते हो? रविता ने कहा- मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनका ख्याल रखा जाए। फिर वह चुप हो गई।रे मां-बाप बूढ़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। उनकी देखभाल में कोई कमी न रहे। इसके बाद दोनों फूट-फूट कर रोने लगे।12 जयवीर सिंह नागर ने नीला ड्रम हत्याकांड का नाम लिए बगैर कहा- केवल काट डालना ही जघन्य अपराध नहीं है। जज ने फैसले में सती सावित्री का जिक्र किया। कहा-पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी करवाचौथ का व्रत करती है, लेकिन यहां प्रेमी के साथ ये कृत्य किया जो



माफी लायक नहीं है। जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और पेन तोड़कर फेंक दिया।मेरठ कोर्ट ने पिछले 3 दिन में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

अभिजीत दीपके-नेहा बोरा हिरासत में



नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दीपके तिरंगा रैली में शामिल होने सेंट्रल पार्क जा रहे थे। 6 दिनों में दीपके को दूसरी बार कस्टडी में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दीपके को विमान से हिरासत में लिया गया था, अगले दिन छोड़ दिया गया। नई दिल्ली जिले में की धारा 163 लागू है। यानी 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

सरकार इस महीने संसद का स्पेशल सेशन बुला सकती है

लोकसभा सीटें बढ़ाने और परिसीमन बिल पेश करने का अनुमान, एनडीए के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें लोकसभा सीटें बढ़ाने के लिए संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन (संशोधन) बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल को पास कराया जाएगा। इनके जरिए महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। 6 महीने (16 और 17 अप्रैल) पहले सरकार पहले



प्रयास में कामयाब नहीं रही थी और लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटा नहीं पाई थी। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने संख्याबल जुटा लिया है। विशेष सत्र बुलाने से करीब एक हफ्ते पहले इसकी सूचना दी जा सकती है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हुआ था, लेकिन इसका अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है।

लोकसभा में 20 और राज्य सभा में 9 सांसदों की जरूरत

लोकसभा में 543 सांसद हैं। 3 सीटें खाली हैं। इनमें से एनडीए के 318 सांसद हैं। बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई यानी 360 वोट चाहिए। अगर डीएमके के 22 सांसद बिल का समर्थन करते हैं तो बिल के समर्थन में 340 सांसद हो जाएंगे। यानी इसके बाद भी भाजपा को लगभग 20 सांसदों की जरूरत है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं। 3 खाली हैं। इस तरह 240 में से एनडीए के 153 सांसद हैं।

खड़गे का मोदी को पत्र, सर्वदलीय बैठक बुलाएं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिसीमन बिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव संसद में रखने से पहले सभी दलों से चर्चा होनी चाहिए।

मुंबई में मिलेंगे रूबियो और जयशंकर

यूएई के विदेश मंत्री भी आएंगे

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20 अक्टूबर 2026 को मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वार्ता करेंगे। वह अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। इससे पहले 19 और 20 अक्टूबर को वह यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की मेजबानी करेंगे। वहीं, अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ घृणा अपराधों और नस्लीय भेदभाव पर भारत ने चिंता जताते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान 19 और 20 अक्टूबर को मुंबई के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर उनकी मेजबानी करेंगे।

महाराष्ट्र में पटाखे पूरे साल बैन, बनाने-बेचने पर रोक नहीं

दिवाली-क्रिसमस में नहीं फोड़ सकेंगे बम

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर लगी रोक पूरे साल लागू कर दी। यह रोक नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और अन्य सभी त्योहारों पर लागू होगी। आदेश पूरे महाराष्ट्र में त्योहारों के जुलूसों के दौरान शोर और वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिया गया है। जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोकले की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। बेंच ने कहा, जब तक नागरिक हालात की जरूरत को नहीं समझेंगे और शहरों में रहने के लंबे समय के खतरों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हालात बिगड़ते रहेंगे। ऐसे शहर गैस चैंबर में बदल सकते हैं।



बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- प्रदूषण से शहर गैस चैंबर बन सकते हैं

गणेशोत्सव में दिया था आदेश

खंडपीठ ने 22 सितंबर के अपने आदेश का दायरा बढ़ाया। यह आदेश गणेशोत्सव के दौरान दिया गया था। कोर्ट ने त्योहारों के जुलूसों के दौरान गंभीर शोर और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह रोक लगाई थी। अब यह आदेश पूरे साल लागू रहेगा।कोर्ट ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई। जजों ने कहा कि कानून का पालन नहीं होना समस्या है।

सरकार का बड़ा फैसला

डीजल के निर्यात पर टैक्स 16 रुपए प्रति लीटर घटाया

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने आज से पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर टैक्स 16 रु. प्रति लीटर से घटाकर 8.50 रु. प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स 0.50रु. से बढ़ाकर 2.50 रु. प्रति लीटर कर दिया गया है। यह बदलाव सिर्फ विदेशों में बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू होगा। इसका घरेलू बाजार में बिकने वाले ईंधन की कीमतों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। यानी आपके शहर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के दाम इस फैसले से सीधे नहीं बदलेंगे।

सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए इस टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में करती है। इसका मकसद देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और तेल कंपनियों को घरेलू बाजार के बजाय विदेशों में ज्यादा ईंधन बेचने से रोकना है।

क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमत

सरकार के फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे? फिलहाल राहत की बात यह है कि निर्यात पर टैक्स की दरें बदलने का मतलब घरेलू बाजार में ईंधन महंगा होना नहीं है। सरकार के फैसले में देश के अंदर बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली ड्यूटी में बदलाव नहीं किया गया है।

नेहा बोरा के 'बांग्लादेश ने हमें रास्ता दिखाया' बयान पर सियासी घमासान

भाजपा ने लगाया 'रिजीम चेंज' का आरोप, राहुल गांधी से पूछे सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)

बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताने वाले अखिल भारतीय छात्र संघ (अईसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के बयान ने देश में गंभीर राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है।

बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए दिए गए वीडियो संदेश में बोरा ने वहां के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश के जेन -जेड आंदोलन ने भारत के युवाओं को रास्ता दिखाया है। इस बयान के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके साथ जुड़े विपक्षी आंदोलन की रणनीति पर सवाल उठाए हैं।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में जुलाई 2024 में शुरू हुआ छात्र आंदोलन आरक्षण के मुद्दे से आगे बढ़कर व्यापक सरकार-विरोधी आंदोलन में बदल गया था। 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को ना सिर्फ पद छोड़ना पड़ा, बल्कि किसी तरह जान बचाते हुए देश छोड़कर जाना पड़ा था। उसी आंदोलन का उदाहरण देते हुए



नेहा बोरा ने भारतीय युवाओं के लिए उसे प्रेरणा बताया है। बता दें नेहा बोरा ने अपने एक वीडियो बयान में बांग्लादेश के छात्र आंदोलन से प्रेरणा लेने की बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि The Gen Z movement we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh and congratulations to you for showing us the way जिसका भावार्थ है भारत में जगह-जगह दिखाई दे रहा ये जेन -जेड आंदोलन सबसे पहले बांग्लादेश में शुरू हुआ और वहां के युवाओं ने हमें रास्ता दिखाया है। यही नहीं नेहा बोरा ने अपने बयान में बांग्लादेश के आंदोलन को लोकतंत्र और मतदाताओं के अधिकारों की लड़ाई बताया। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के युवाओं के साझा संघर्ष तथा धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई का भी उल्लेख किया। यह बयान उन्होंने 14 अक्टूबर को बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया था।

भाजपा का सवाल: लोकतांत्रिक विरोध या सत्ता परिवर्तन की रणनीति?

इस बयान के सामने आने के बाद भाजपा ने नेहा बोरा के बयान को केवल छात्र आंदोलन से प्रेरणा लेने तक सीमित नहीं माना है बल्कि कहा है कि राहुल गांधी और उनसे जुड़े राजनीतिक समूह भारत में बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां पैदा कर भारत की अस्थिर करने के लिए सत्ता परिवर्तन की मंशा रखते हैं कि भाजपा ने कहा है कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का परिणाम तत्कालीन सरकार के पतन के रूप में सामने आया था। ऐसे में भारत के मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को उसी आंदोलन से प्रेरित बताने वाले बयान पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रेरणा का आशय और उद्देश्यों क्या है। नेहा के इस नयन के बाद बांग्लादेश के घटनाक्रम को समझना जरूरी हो जाता है कि जब जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान बांग्लादेश में सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसके बाद वहां के लोगों कोकगास कर हिंदुओं को किस तरह से हिंसा, जानमाल का नुकसान और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा था। उसके बाद समय की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद देश में अंतरिम शासन व्यवस्था बनी और वहाँ की कानून-व्यवस्था की स्थिति अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता के विरुद्ध अब तक बनी है।

सिंहस्थ आरक्षित भूमि पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

महामंडलेश्वर ज्योतिगिरि के अवैध आश्रम पर चला बुलडोजर

उज्जैन। धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार तड़के नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्कराज पार्किंग और नृसिंहघाट क्षेत्र के समीप स्थित जूना अखाड़े के हरियाणा सेवा आश्रम पर बुलडोजर चला दिया। महामंडलेश्वर ज्योतिगिरिजी महाराज द्वारा सिंहस्थ की सुरक्षित जमीन पर होटलनुमा अवैध सुबह-सुबह पोकलेन और जेसीबी से हुई कार्रवाई नगर निगम के भवन अधिकारियों के अनुसार, निगम की टीम ने पूरी योजना के तहत सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच मौके पर दबिश दी। इस विशाल ढांचे को गिराने के लिए चार पोकलेन मशीनों और एक जेसीबी का इस्तेमाल किया गया।

त्योहारों के मद्देनजर सफाई व्यवस्था की विशेष मॉनिटरिंग करें - स्वास्थ्य प्रभारी श्री सत्यनारायण चौहान



उज्जैन। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सदस्य श्री सत्यनारायण चौहान द्वारा गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शहर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने तथा नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।

श्री चौहान ने कहा कि त्योहारों के दौरान शहर में स्वच्छता बनाए रखना प्राथमिकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सफाई व्यवस्था की सतत निगरानी करें। कमर्शियल क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखें साथ ही शहर में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों में भी विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपने निर्देशित किया कि हाट बाजार समाप्त होने के बाद दुकानदार अपनी दुकानों से निकलने वाला कचरा, फल एवं सब्जियों के अवशेष निर्धारित स्थान पर ही डालें, ताकि बाजारों में गंदगी न फैले।

प्रभारी सदस्य श्री चौहान ने कहा कि दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाए। हाट बाजारों में कचरा संग्रहण के लिए निर्धारित स्थल पर एक अतिरिक्त कचरा संग्रहण वाहन खड़ा रखने की व्यवस्था की जाए, जिससे बाजार समाप्त होने के पश्चात दुकानदार आसानी से अपना कचरा वाहन में डाल सकें।

श्री चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए कि समझाइश के बावजूद खुले में कचरा फेंकने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी चालानी कार्रवाई की जाए। साथ ही बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को हाट बाजार में दुकान लगाने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के सभी हाट बाजारों में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए नियमित निरीक्षण किया जाए यदि अतिरिक्त सफाई मित्रों की आवश्यकता है तो उनसे सफाई कार्य संपादित करवाया जाए।

बैठक में सहायक आयुक्त श्री राघवेंद्र सिंह पालिया, स्वास्थ्य अधिकारी श्री आनंद विजय सिंह राठौर एवं स्वच्छता निरीक्षक उपस्थित रहे।

सिंहस्थ 2028- कर्कराज पार्किंग से नरसिंह घाट तक प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण कार्य का संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने निरीक्षण किया



उज्जैन। आगामी सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में संभाग आयुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह और कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने नियमित निरीक्षण के तहत गुरुवार को कर्कराज पार्किंग क्षेत्र से नरसिंह घाट तक प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण कार्य एवं पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान संभाग आयुक्त श्री सिंह ने नगर निगम के इंजीनियरों से इस महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण कार्य की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सिंहस्थ महापर्व की महत्ता को देखते हुए इस मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए और इसे निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण के साथ पूर्ण किया जाये।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बेहोश पड़े थे नारायण जन सेवा प्रहरी ने अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई



उज्जैन । पंद्रह अक्टूबर सुबह 10ः45 बजे राघौपिपलिया निवासी राजेंद्र सिंह चौहान, जो कि जन सेवा प्रहरी भी हैं, किसी काम से गंगेडी के पास से होकर गुजर रहे थे। अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक बुलेट मोटरसाइकिल गिरी हुई दिखी और साइड में एक 35 से 40 वर्ष के युवा बेहोश पड़े हुए दिखे। अज्ञात वाहन नारायण को टक्कर मारकर भाग गया था।

जन सेवा प्रहरी श्री राजेंद्र सिंह चौहान ने तुरंत अपने गांव के सरपंच से चार पहिया वाहन मंगवाया और उसमें नारायण को लेकर अवंति अस्पताल पहुंचे। अवंति अस्पताल में एक्सीडेंट के कुछ ही समय, जिन्हें गोल्डन ऑवर कहा जाता है, नारायण का उपचार शुरू हो गया और उनकी जान बच गई। राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही जन सेवा प्रहरी योजना अब एक्सीडेंट में लावारिस और बेहोश पड़े हुए व्यक्तियों की जान बचाने में बेहद कारगर सिद्ध हो रही है।

जन सेवा प्रहरी राजेंद्र सिंह चौहान बताते हैं कि जन सेवा प्रहरियों को इस कार्य के लिए अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है। वे बिना किसी डर के सीधे एक्सीडेंट पीड़ित लोगों को अस्पताल में पहुंचा रहे हैं और इस कार्य के लिए उन्हें सराहना प्रमाण पत्र व 25 हजार रूपए का आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

साथ ही अस्पताल कर्मी उनके साथ अच्छा सहयोग करते हैं, पुलिस की ओर से कोई पूछताछ की नहीं की जाती । राजेंद्र सिंह कहते हैं कि इस योजना में प्रशिक्षित व्यक्ति के अलावा यदि कोई आम व्यक्ति भी किसी की सहायता करता है, तो उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है और प्रोत्साहन अलग से मिलता है। इसलिए हमें एक्सीडेंट दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की हर संभव सहायता करनी चाहिए।

जिला स्तरीय युवा उत्सव-2027 के लिए पंजीयन प्रारंभ, 28 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

उज्जैन । खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय युवा उत्सव-2027 के अंतर्गत उज्जैन जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन अक्टूबर 2026 में किया जा रहा है। उत्सव में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। आयोजन की थीम 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' रखी गई है। युवा उत्सव में समूह लोकनृत्य, समूह लोकगीत, पेंटिंग, कविता लेखन एवं नुक्कड़ नाटक सहित पांच विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला स्तरीय आयोजन के बाद नवंबर 2026 में संभाग स्तरीय आयोजन होगा। जिला स्तर पर चयनित युवा एवं दल संभाग स्तर पर तथा संभाग स्तर पर चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। राज्य स्तर पर चयनित युवा एवं दल राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेंगे। राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुसार, युवा उत्सव में भाग लेने के लिए 28 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग, देवास रोड, उज्जैन में जमा करना होगा। इसके साथ ही स्व ब्बद्धड्डह्लड्डह्ल क्कह्लह्लड्डद्य पर पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार गत वर्ष युवा उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले चुके युवा इस वर्ष प्रतिभागिता नहीं कर सकेंगे। साथ ही, एक प्रतिभागी केवल एक ही विधा में भाग ले सकेगा।

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से रियाज को मिला नया जीवन



उज्जैन । आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जरूरतमंद बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के माध्यम से उज्जैन के जानसापुरा निवासी दो वर्षीय रियाज के हृदय का निःशुल्क ऑपरेशन कर उसे नया जीवन मिला है। अब रियाज पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जीवन जीने की ओर अग्रसर है। जानसापुरा निवासी श्री नौशाद एवं श्रीमती संजना का बेटा रियाज जन्म से ही कमजोर था। वह थोड़ा खेलने पर ही थक जाता था और उसकी सांस फूलने लगती थी। अन्य बच्चों की तरह उसका शारीरिक विकास भी नहीं हो रहा था। वह अक्सर बीमार रहता था, जिससे उसके माता-पिता काफी चिंतित रहते थे। इसी दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की मोबाइल हेल्थ टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्क्रीनिंग के दौरान चिकित्सक ने रियाज की जांच की। जांच में उसके हृदय रोग से ग्रसित होने की जानकारी मिली। इसके बाद आरबीएसके दल के चिकित्सक ने रियाज को तत्काल उज्जैन रेफर किया और उसके माता-पिता को जिला चिकित्सालय स्थित जिला स्तरीय शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) में उपचार कराने की सलाह दी। उन्हें बताया गया कि मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत रियाज का निःशुल्क ऑपरेशन कराया जा सकता है। इसके बाद रियाज के माता-पिता उसे लेकर जिला चिकित्सालय उज्जैन स्थित डीईआईसी पहुंचे। यहां आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना में उसका पंजीयन किया गया तथा आवश्यक जांचें कराई गईं। इसके बाद रियाज को इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसके हृदय का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन पर हुए संपूर्ण खर्च का वहन मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत किया गया। वर्तमान में रियाज पूरी तरह स्वस्थ है और उसका नियमित फॉलोअप लिया जा रहा है। समय पर पहचान, उचित उपचार और शासन की योजना से रियाज को स्वस्थ जीवन की नई उम्मीद मिली है। रियाज के माता-पिता ने अपने बेटे के सफल उपचार और ऑपरेशन का पूरा खर्च शासन द्वारा वहन किए जाने पर मध्यप्रदेश शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक चिंता से राहत देकर बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और सामान्य जीवन का अवसर प्रदान कर रही है।

आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में एड्स कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित



उज्जैन । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम रघुवंशी के निर्देशानुसार 14 अक्टूबर 2026 को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज स्थित एआरटी सेंटर में एड्स कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एचआईवी संक्रमण के प्रति जागरूकता अभियान की समीक्षा की गई तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। एड्स कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. अरुण कुशवाह ने बताया कि एचआईवी कार्यक्रम के अंतर्गत 12 अगस्त से 12 अक्टूबर 2026 तक सघन जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा ग्राम स्तरीय बैठकों के माध्यम से लोगों को एचआईवी-एड्स के प्रति जागरूक किया गया। अभियान में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले शत-प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गई। बैठक में मिशन एड्स सुरक्षा (एमएएस) के अंतर्गत कार्यरत समस्त स्टाफ एवं एनजीओ प्रतिनिधियों को एचआईवी कार्यक्रम के 95ः95ः95 लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। डॉ. कुशवाह ने कहा कि पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हाई रिस्क क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाकर एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन एचआईवी संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है, उन्हें नियमित उपचार एवं दवा उपलब्ध कराने के लिए एआरटी सेंटर से जोड़ा जाए, ताकि दूसरे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बैठक में एचआईवी संक्रमण की जांच, मरीजों को उपचार से जोड़ने तथा जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया गया।

युवराज को मिला नया जीवन, 2.50 लाख रुपये का ऑपरेशन निःशुल्क हुआ आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन ने उठाया हृदय के ऑपरेशन का पूरा खर्च



उज्जैन । आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के माध्यम से उज्जैन जिले के उन्हेल निवासी तीन वर्षीय युवराज के हृदय का सफल ऑपरेशन निःशुल्क कराया गया। ऑपरेशन पर खर्च हुए 2 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया। अब युवराज पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जीवन जी सकेगा।

उन्हेल निवासी कृषि कार्य करने वाले श्री कुलदीप सिंह एवं श्रीमती निर्मला का तीन वर्षीय पुत्र युवराज अधिक खेलने पर थक जाता था और उसकी सांस फूलने लगती थी। अन्य बच्चों की तरह उसका शारीरिक विकास भी नहीं हो रहा था। वह अक्सर बीमार रहता था, जिससे उसके माता-पिता काफी चिंतित रहते थे। इसी दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की मोबाइल हेल्थ टीम गांव में भ्रमण कर रही थी। आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्क्रीनिंग के दौरान चिकित्सक ने युवराज की जांच की। जांच में उसके हृदय में छेद होने की जानकारी मिली।

आरबीएसके दल के चिकित्सक ने युवराज के माता-पिता को समझाया कि बचपन में ही ऑपरेशन होने से भविष्य में उसे सामान्य जीवन जीने में परेशानी नहीं होगी। इसके बाद युवराज को तत्काल उज्जैन रेफर किया गया तथा उसके माता-पिता को जिला चिकित्सालय स्थित जिला स्तरीय शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) में उपचार कराने की सलाह दी गई। युवराज के माता-पिता उसे लेकर जिला चिकित्सालय उज्जैन स्थित डीईआईसी पहुंचे। यहां आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना में उसका पंजीयन कर आवश्यक जांचें कराई गईं। इसके बाद युवराज को इंदौर के विशेष हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसके हृदय का सफल ऑपरेशन किया गया।

ऑपरेशन पर हुए 2 लाख 50 हजार रुपये के संपूर्ण खर्च का वहन मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया। वर्तमान में युवराज पूरी तरह स्वस्थ है और उसका नियमित फॉलोअप लिया जा रहा है। समय पर बीमारी की पहचान, उचित उपचार और शासन की योजना से युवराज को स्वस्थ जीवन की नई उम्मीद मिली है। युवराज के माता-पिता ने अपने बेटे के सफल उपचार और ऑपरेशन का पूरा खर्च शासन द्वारा वहन किए जाने पर मध्यप्रदेश शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता मिल रही है तथा बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और सामान्य जीवन जीने का अवसर मिल रहा है।

जिला चिकित्सालय में 15 अक्टूबर से चेस्ट क्लिनिक का संचालन प्रारंभ

वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की जांच, उपचार एवं परामर्श की मिलेगी सुविधा

उज्जैन। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (ह्वह्वष्ट॥॥) के अंतर्गत जिला चिकित्सालय उज्जैन के चरक भवन में 15 अक्टूबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक चेस्ट क्लिनिक का संचालन किया जाएगा। यहां वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की स्क्रीनिंग, जांच, उपचार, परामर्श एवं फॉलोअप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. संगीता पलसानिया, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि चेस्ट क्लिनिक के माध्यम से सभी आयु वर्ग के मरीजों में वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर जोखिम का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर मरीजों को आवश्यक उपचार एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि धूम्रपान, घरेलू ईंधन से निकलने वाले धुएं, धूल, औद्योगिक प्रदूषण एवं अन्य प्रदूषण स्रोतों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की विशेष रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही मरीजों को वायु प्रदूषण से बचाव, धूम्रपान छोड़ने, स्वच्छ ईंधन के उपयोग, घरों में उचित वेंटिलेशन बनाए रखने तथा अधिक प्रदूषण वाले दिनों में सावधानी बरतने के संबंध में जागरूक किया जाएगा। आवश्यकतानुसार मरीजों को संबंधित विशेषज्ञ सेवाओं एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें समय पर उचित उपचार मिल सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार तथा आमजन में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। चेस्ट क्लिनिक के संचालन से वायु प्रदूषण के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम एवं नियंत्रण में सहायता मिलेगी।

डॉ. डी. डी. बेदिया के कुलगुरु बनने पर शिक्षक संघ ने आयोजित किया सम्मान समारोह



उज्जैन । सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन में डॉ. डी. डी. बेदिया के बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलगुरु नियुक्त होने पर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलगुरु डॉ. शैलेंद्र कुमार शर्मा ने की।

समारोह में डॉ. दीपक गुप्ता ने अपने संबोधन में डॉ. बेदिया के उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों की विस्तार से विवेचना की। इस अवसर पर पं. जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के निदेशक डॉ. धर्मेंद्र मेहता, कुलसचिव डॉ. अनिल कुमार शर्मा, सहायक कुलसचिव श्री गौरी शंकर बरार तथा शिक्षक संघ की अध्यक्ष डॉ. कनिया मेड़ा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. बेदिया के साथ जुड़े अनुभवों और स्मृतियों को साझा किया। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए प्रभारी कुलगुरु डॉ. शर्मा ने विश्वविद्यालय में डॉ. बेदिया की 19 वर्षों की दीर्घ सेवा यात्रा का सजीव चित्रण किया।

उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अपने सम्मान के प्रति उत्तर में डॉ. डी. डी. बेदिया ने सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभी के सहयोग से आगे कार्य करने का संकल्प जताया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राज बोरिया ने किया तथा अंत में आभार प्रदर्शन महाराजा जीवाजीराव पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार जैन ने किया। इस समारोह में वित्त नियंत्रक श्री जे एस तोमर, परीक्षा नियंत्रक प्रो. एम द्विवेदी, डॉ. उमेश कुमार सिंह, डॉ. संदीप तिवारी, डॉ. दशोरा, डॉ. टेलर, डॉ. स्वाति दुबे, डॉ. वी. जे. परमार, डॉ. सलिल सिंह, डॉ. वीरेंद्र चावरे, डॉ. निश्चल यादव एवं श्री संजू सिंह सहित विश्वविद्यालय के अनेक अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कान्ह डायवर्सन का कार्य मई 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश

उज्जैन । संभागायुक्त श्री आशीष सिंह ने आज सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण तथा जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट, अपर आयुक्त नगर निगम श्री संतोष टेगौर, अपर मेला अधिकारी श्री ओमप्रकाश सनोडिया, उप मेला अधिकारी श्री संदीप सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे सिंहस्थ के प्रमुख कार्यों में चौराहों का विकास, मंगलनाथ मंदिर का विकास, कालभैरव मंदिर का विकास, अंगारेश्वर-सिद्धवट का विकास, अंकपात से खाक चौक तक का चौड़ीकरण, शक्करवासा से छोटी रपट पंचक्रोशी मार्ग, कालिदास अकादमी में डोम शेड का निर्माण तथा शनि मंदिर से जीवनखेड़ी तक की सड़क का निर्माण आदि शामिल हैं।

जन्मजात विकृति से मिली मुक्ति अब सामान्य बच्चों की तरह मुस्कुराती है छह माह की संजना, परिवार ने शासन का जताया आभार



उज्जैन । राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) जरूरतमंद बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के ग्राम बोलखेड़ा निवासी छह माह की संजना के कटे होंठ (क्लैफ्ट लिप) का निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया। सफल ऑपरेशन के बाद संजना के होंठ का आकार सामान्य होने लगा है और अब वह सामान्य बच्चों की तरह मुस्कुराती है। ग्राम बोलखेड़ा निवासी श्री शिवसिंह ठाकुर मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनकी बेटी संजना जन्मजात विकृति से ग्रसित थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसके माता-पिता ऑपरेशन के खर्च को लेकर चिंतित थे। इसी दौरान क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच एवं स्क्रीनिंग की जा रही थी। इस दौरान टीम ने संजना की भी जांच की, जिसमें उसके होंठ कटे होने की जानकारी मिली। आरबीएसके के चिकित्सक ने संजना के माता-पिता को समझाया कि बचपन में ही ऑपरेशन होने से भविष्य में उसे बोलने तथा खाने-पीने में होने वाली परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी और उसके होंठ का आकार भी सामान्य हो सकेगा।

संजना के माता-पिता ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऑपरेशन के खर्च को लेकर चिंता जताई। इस पर चिकित्सक ने उन्हें बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संजना का निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा तथा उन्हें इसके लिए कोई खर्च नहीं करना होगा। चिकित्सक की समझाइश के बाद माता-पिता ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। आरबीएसके चिकित्सक ने संजना को तत्काल जिला चिकित्सालय उज्जैन स्थित जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) रेफर किया। यहां से उसे इंदौर के एनएस हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसके कटे होंठ का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद संजना के होंठ का आकार धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है।

उमरिया जिले के जनपद पंचायत मानपुर के ग्राम पंचायत गुरुवाही में मूख्यमंत्री के कार्यक्रम से वरिष्ठ भाजपा नेताओं की दूरियां

जिले के ग्राम पंचायत गुरुवाही में कुर्सी कांड से भाजपा में भूचाल

उमरिया(अविरल गौतम)

उमरिया। जिले के मानपुर विधानसभा के ग्राम गुरुवाही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कार्यक्रम तो बड़े जोर-शोर से हुआ, टेंट तना था, मंच चमक रहा था, माइक गूंज रहा था, लेकिन उस चमकते मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए कुर्सी ही नहीं लगी थी, और बस इसी एक कुर्सी ने जिले की पूरी सियासत में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी चर्चा हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान और हर व्हाट्सएप ग्रुप पर हो रही है, दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंच पर गिनती की कुर्सियां लगाई गई थीं और उन कुर्सियों पर सिर्फ चुनिंदा और चहेते चेहरों को ही बैठाने की व्यवस्था थी, जिले के वरिष्ठ नेताओं के लिए कुर्सी लगाई ही नहीं गई थी तो वे आते भी तो कहां बैठते, इसी अपमान से आहत होकर वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बना लेना ही बेहतर समझा, यह दूरी सिर्फ नाराजगी नहीं थी, यह एक सियासी संदेश था कि सम्मान के बिना भीड़ बढ़ाने का जमाना अब गया।

इस कुर्सी कांड के सबसे बड़े शिकार बने उमरिया में भाजपा का पर्याय माने जाने वाले कद्दावर आदिवासी नेता ज्ञान सिंह, जिनका नाम उमरिया की राजनीति में इतिहास की तरह लिया जाता है, जब प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चलती थी तब भी ज्ञान सिंह अकेले भगवा झंडा थामे खड़े रहते थे, उन्होंने भाजपा को उमरिया में खड़ा किया, सींचा और सत्ता तक पहुंचाया, आज उसी अपराजेय योद्धा के लिए अपने ही जिले के भाजपा कार्यक्रम में, जहां आदिवासी बहन सुश्री मीना सिंह विधायक हैं, उनके क्षेत्र के कार्यक्रम में एक कुर्सी तक नहीं थी, तो वे क्यों आते, बताते हैं कि ज्ञान सिंह ने भी सोच लिया था कि जब सम्मान ही नहीं तो जाकर भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा, यह बात सिर्फ ज्ञान सिंह की नहीं है, यह उस पीढ़ी की पीड़ा है जिसने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया और आज उसी पार्टी के मंच पर उनके लिए जगह नहीं बची।



यह अपमान सिर्फ ज्ञान सिंह तक सीमित नहीं रहा, पूरे मंच पर एक भी ब्राह्मण नेता के लिए कुर्सी नहीं थी, मानपुर विधानसभा जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, वहां उनके नेताओं के लिए मंच पर जगह ही नहीं थी, अब यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बताकर संगठन की सोची-समझी रणनीति थी या ब्राह्मण नेतृत्व को जानबूझकर हाशिये पर धकेलने की नई परंपरा, यह तो भाजपा ही जाने लेकिन चर्चा यही है कि कुर्सी न होने के कारण ही ब्राह्मण चेहरों ने भी किनारा कर लिया, राजनीति में संदेश बहुत मायने रखता है, और गुरुवाही का संदेश साफ था, पुराने चेहरे अब मंच के लायक नहीं रहे, नए चहेते ही मंच के हकदार हैं।

इसी बीच पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप पांडेय और पूर्व महामंत्री अरुण चतुर्वेदी आखिरी समय तक मंच की गणेश परिक्रमा करते देखे गए, इस आस में कि शायद कहीं एक कुर्सी खाली मिल जाए, लेकिन जब कुर्सी लगाई ही नहीं गई थी तो मिलती कहां से, उनकी परिक्रमा भी व्यर्थ चली गई, दिलीप पांडेय ने तो फिर भी हिम्मत दिखा दी, बाकी पूर्व जिलाध्यक्षों ने तो पहले ही भांप लिया था कि मंच पर जगह नहीं है और घर में दुबकने में ही भलाई समझी, इतना ही नहीं मोर्चा और प्रकोष्ठों के वर्तमान पदाधिकारियों तक के लिए मंच पर कोई कुर्सी नहीं थी, यानी संगठन की पूरी सीढ़ी ही मंच से बाहर थी, सिर्फ शीर्ष के कुछ चेहरे मंच पर थे, बाकी सब दर्शक दीर्घा में, यह कौन सा संगठन का अनुशासन है जहां कार्यकर्ता को ही मंच से बेदखल कर दिया जाए।

अब लोग पूछ रहे हैं कि मंच पर कुर्सियां सिर्फ लक्ष्मीपतियों और कुबेरपतियों के लिए ही सुरक्षित थीं क्या, बाकी निष्ठावान कार्यकर्ताओं और वरिष्ठों के लिए भाजपा में अब कोई जगह ही नहीं बची, जब वरिष्ठों को ही कुर्सी नसीब नहीं तो आम कार्यकर्ता किस उम्मीद में पसीना बहाए, यही सवाल आज उमरिया भाजपा में सबसे बड़ा तंज बन गया है, कार्यकर्ता पूछ रहा है कि क्या भाजपा अब विचारधारा की पार्टी नहीं, बल्कि व्यवस्था की पार्टी बन गई है, जहां कुर्सी उसी को मिलेगी जो व्यवस्था के करीब होगा, निष्ठा और संघर्ष का अब कोई मोल नहीं रहा।

और इस कुर्सी कांड का सबसे तीखा और सबसे दर्दनाक पहलू अभी बाकी है, मंच पर आदिवासी नेत्री ज्ञानवती सिंह को स्थान तो मिल गया था, लेकिन मंच से उद्बोधन में किसी ने नाम लेकर संबोधन करना उचित नहीं समझा, यह अपमान कुर्सी न मिलने से भी बड़ा अपमान है, क्योंकि कुर्सी न मिलना तो दिखता है, लेकिन मंच पर बैठकर भी नाम न लिया जाना, वह भीड़ में बैठकर भी अकेला कर देने जैसा है, ज्ञानवती सिंह वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं, जो लगातार दोबारा बनी हुई हैं, यद्यपि इसके पहले वह कांग्रेस में थीं और कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ती रही हैं, सुश्री ज्ञानवती सिंह इसके पूर्व लगातार दो पंचवर्षीय जिला पंचायत उमरिया की अध्यक्ष रहीं, उनके राजनीतिक इतिहास में जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों का निर्वहन उन्होंने बखूबी किया है, बावजूद इसके कांग्रेस से होने के कारण आज भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण न स्थानीय वक्ताओं ने और न ही मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम का उद्बोधन में उल्लेख किया, यानी मंच पर बैठीं ज्ञानवती सिंह को मंच से ही अदृश्य कर दिया गया, यह कैसा सम्मान है, यह कैसी समरसता है, यह कैसा सबका साथ है, जहां प्रदेश कार्य समिति की सदस्य का नाम लेने में भी परहेज किया जाए।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री के इस शासकीय कार्यक्रम में हुए इस कुर्सी कांड में भूमिका किसकी थी, प्रशासन की या जनप्रतिनिधियों की, यह तो पर्दे के पीछे छिपा है, लेकिन सच्चाई यही है कि शासकीय कार्यक्रम में मंच की व्यवस्था, प्रोटोकॉल, बैठने की व्यवस्था और नामों के उल्लेख की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, और राजनीतिक समन्वय की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और संगठन की होती है, जब दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो अपमान की ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी, पर्दे के पीछे बैठकर किसने किसका नाम कटवाया, किसने किसकी कुर्सी हटवाई, यह तो जांच का विषय है, लेकिन परिणाम तो सबके सामने है, वरिष्ठ नेता नाराज हैं, कार्यकर्ता आहत है, और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, इसलिए मुख्यमंत्री को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कार्यक्रम की चूक नहीं है, यह सरकार की कार्यशैली पर सवाल है।

दरअसल गुरुवाही का यह घटनाक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम की अव्यवस्था नहीं है, यह उमरिया भाजपा के अंदर पनप रही गहरी खाई का प्रतीक है, एक तरफ नए और चहेते चेहरों का जमावड़ा है, दूसरी तरफ पुराने, अनुभवी और जमीन से जुड़े नेताओं की उपेक्षा है, एक तरफ आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाम पर ब्राह्मण नेतृत्व को दरकिनार करने की चर्चा है, दूसरी तरफ आदिवासी नेत्री को ही मंच पर नाम से वंचित करने की सच्चाई है, यानी संतुलन कहीं नहीं है, सिर्फ गुटबाजी है, सिर्फ चापलूसी है, सिर्फ कुर्सी की राजनीति है, और यही गुटबाजी भाजपा को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में न आना सिर्फ नाराजगी नहीं, संगठन के लिए एक चेतावनी है, भाजपा नेतृत्व को इसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए, वरना भाजपा को कांग्रेस बनने में देर नहीं लगेगी, कांग्रेस भी कभी इसी कुर्सी की राजनीति, इसी उपेक्षा और इसी अहंकार के कारण टूटी थी, आज वही बीमारी भाजपा में फैलती दिख रही है, अगर समय रहते इस कुर्सी कांड से सबक नहीं लिया गया, अगर ज्ञान सिंह जैसे योद्धाओं को, ब्राह्मण नेतृत्व को, पूर्व जिलाध्यक्षों को, मोर्चा-प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को और ज्ञानवती सिंह जैसी अनुभवी नेत्री को सम्मान नहीं दिया गया, तो आने वाले चुनाव में यह नाराजगी वोट की चोट बनकर सामने आएगी, क्योंकि कार्यकर्ता मंच पर कुर्सी नहीं मांगता, वह सिर्फ सम्मान मांगता है, और जब सम्मान ही छीन लिया जाए तो कार्यकर्ता घर बैठ जाता है, और घर बैठा कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, इसलिए मुख्यमंत्री को आगे से ऐसी पुनरावृत्ति पर रोक लगानी ही होगी, मंच व्यवस्था के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय करना होगा, वरिष्ठों, पूर्व पदाधिकारियों और प्रदेश कार्य समिति सदस्यों के सम्मान की गारंटी करनी होगी, ताकि गुरुवाही जैसा कुर्सी कांड फिर कभी न दोहराया जाए, गुरुवाही ने यह खतरे की घंटी बजा दी है, अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व इस घंटी को सुनता है या फिर इसे भी एक सामान्य घटना मानकर अनसुना कर देता है।

सोहागपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई: देर रात हुड़दंग मचा मारपीट करने वाले आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा,कानून व्यवस्था सख्त

शहडोल(अविरल गौतम)

शहडोल। जिले की सोहागपुर थाना पुलिस ने त्वरित एवं अनुशासित कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था बिगाड़ने और मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई के सामने होमगार्ड कॉलोनी में देर रात अवैध रूप से उपद्रव मचाने और छात्रों/युवकों के साथ मारपीट व धमकी देने के मामले में पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस की इस तत्परता और सख्त संदेश से क्षेत्र के नागरिकों एवं कानून-पसंद लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित अतुल सिंह बघेल (23 वर्ष) पिता बृजेन्द्र सिंह बघेल, निवासी रघुनाथपुर (रीवा) एवं हाल निवासी फॉरेस्ट कॉलोनी गांधी चौक (शहडोल), अपने मित्रों पवन यादव, मो. आफताब, प्रशांत सिंह बघेल और बलवंत बिंद के साथ होमगार्ड मैदान के पीछे स्थित कमरे में मौजूद थे। 7 अक्टूबर की



देर रात लगभग 11:30 बजे असामाजिक तत्वों शौरभ तिवारी, अमिताभ शुक्ला एवं उनके साथियों ने अनाधिकृत रूप से दरवाजा खटखटाकर विवाद खड़ा किया और विरोध करने पर डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटना में पीड़ित को सिर, आंख, नाक, गाल, हाथ और पैरों में चोटें आईं। घटना के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। मुकदमा दर्ज कर जांच अधिकारी नियुक्त, प्रशासन की सख्ती घटना की सूचना मिलते ही सोहागपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज की। थाना प्रभारी निरीक्षक रामायण प्रसाद रावत के निर्देश पर सहायक उपनिरीक्षक शिवराम सिंह ने कायमी कर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 296(b), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले की गहराई से जांच के लिए प्रधान आरक्षक संतोष परिहार को जांच अधिकारी (I.O.) नियुक्त किया गया है। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और रात्रि कालीन उपद्रवियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन का यह सख्त कदम क्षेत्र में सराहा जा रहा है

जिले के ग्राम पंचायत चंदौली के खेत में अवैध कनेक्शन से गई हाथी की जान, बिजली विभाग की शिकायत पर दो पर एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

शहडोल(अविरल गौतम)

शहडोल। जिले के ग्राम पंचायत चंदौली गांव में करंट लगने से नर हाथी की मौत के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। खेत में अवैध बिजली कनेक्शन से बोरवेल चलाया जा रहा था, जिसकी चपेट में हाथी आ गया। घटना के बाद तार काटे जाने से साक्ष्य मिटाने की आशंका भी जताई गई है।

जिले के देवलौंद थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से नर हाथी की मौत के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि खेत में अवैध बिजली कनेक्शन के जरिए बोरवेल चलाया जा रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से हाथी की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बाणसागर में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता अभिनेंद्र सिंह चौहान ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में खेत में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन लेकर बोरवेल चलाए जाने की बात



सामने आई है। इसी कनेक्शन से फैले करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत होने का आरोप है। मामले में पुलिस ने अक्षत सिंह बैंस और देवराज सिंह बैंस के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

12-13 अक्टूबर की रात हुई थी हाथी की मौत

गौरतलब है कि 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात पश्चिम ब्यौहारी वन परिक्षेत्र के चचाई बीट अंतर्गत ग्राम चंदौली में खेत के पास बोरवेल के नजदीक एक हाथी की मौत हुई थी। मृत हाथी करीब 15 वर्ष का नर बताया गया है। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में खेत में बिजली के करंट से जुड़े मामले में कुछ लोगों की भूमिका सामने आने की बात कही गई थी। यह भी आरोप है कि घटना के बाद बिजली का तार काट दिया गया जिससे साक्ष्य मिटाने की आशंका जताई जा रही है।फिलहाल पुलिस ने बिजली विभाग के अधिकारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। अब जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि अवैध बिजली कनेक्शन किसने लिया था और हाथी की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। दो लोगों पर मामला दर्ज कर जांच आगे की जा रही है।

अब सवाल यह उठता है कि पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक हाथियों का विचारण लगातार बना हुआ था, जंगली, पहाड़ी क्षेत्र में हाथी अपना डेरा जमाए हुए थे, जिनकी निगरानी के लिए वन विभाग की विशेष टीमों का गठन किया गया था। लगातार दिन रात हाथियों की मॉनिटरिंग की जा रही थी लेकिन झुंड से अलग होकर एक हाथी खेत में पहुंच गया और वन विभाग को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। अगर उस क्षेत्र की सप्लाई समय से बंद कर दी जाती तो हाथी की जान बच सकती थी।

जिले के नवरोजाबाद में माँ ज्वालाधाम शक्तिपीठ उचेहरा की अद्भुत कहानी, 21 अक्टूबर को होगा देवी जागरण

माँ ज्वाला के प्राकट्य का प्रसंग, नवरात्रि पर कलश स्थापना, जवारा जुलूस एवं विसर्जन के साथ होंगे धार्मिक आयोजन

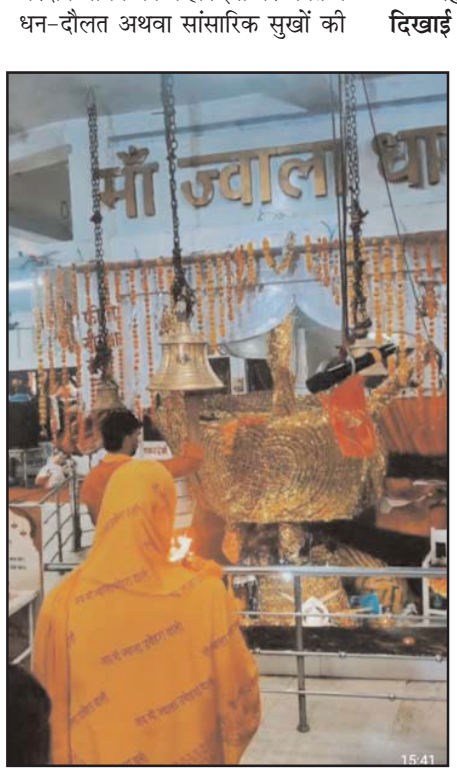
उमरिया (दीपक द्विवेदी)

उमरिया। जिले में नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित माँ ज्वालाधाम शक्तिपीठ, उचेहरा श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। घोड़छत्र नदी के तट और प्राकृतिक परिवेश के बीच स्थित इस पावन धाम की कहानी माँ के अनन्य भक्त की श्रद्धा, समर्पण और नि:स्वार्थ सेवा से जुड़ी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, माँ ज्वाला के प्राकट्य से जुड़ी यह कथा आज भी श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखती है।

भक्त भंडारी सिंह की श्रद्धा से जुड़ी है माँ ज्वाला के प्राकट्य की कथा

स्थानीय मान्यता के अनुसार, प्राचीन समय से ही घोड़छत्र नदी के किनारे घने जंगल में माँ ज्वाला का स्थान रहा है। उचेहरा और आसपास के गांवों के श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना किया करते थे। इसी स्थान से जुड़ी लोककथा उचेहरा निवासी भंडारी सिंह जी की अटूट भक्ति का वर्णन करती है। कथा के अनुसार, भंडारी सिंह जी माँ ज्वाला के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह-शाम जंगल में स्थित माँ के स्थान पर जाकर पूजा करते थे। माँ के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण उनके जीवन का प्रमुख आधार था।

कहते हैं कि एक दिन माँ ज्वाला ने भंडारी सिंह जी को स्वप्न में दर्शन दिए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर भक्त ने धन-दौलत अथवा सांसारिक सुखों की



कामना करने के बजाय माँ से सद्बुद्धि और जीवनभर उनकी सेवा करने का आशीर्वाद मांगा।

लोकमान्यता के अनुसार, भक्त की नि:स्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें अपने स्थान पर मंदिर निर्माण कराने और अपनी आराधना का प्रसार करने का संदेश दिया।

महायज्ञ के दौरान दिव्य प्रकाश दिखाई देने की मान्यता

कथा के अनुसार, माँ के संदेश के बाद भंडारी सिंह जी ने ग्रामवासियों को इसकी जानकारी दी। इसके पश्चात सभी के सहयोग से वर्ष 2006-07 में माँ ज्वालाधाम के मंदिर का निर्माण कराया गया।

मंदिर निर्माण के बाद ग्रामवासियों ने यहां विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। स्थानीय मान्यता के अनुसार, यज्ञ के दौरान एक शाम मंदिर परिसर में अद्भुत आवाज सुनाई दी और दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जो करौंदा वृक्ष में समाहित हो गया।

श्रद्धालु इस प्रसंग को माँ ज्वाला के पुन: प्राकट्य से जोड़कर देखते हैं।

इसके बाद यह स्थान माँ ज्वालाधाम शक्तिपीठ, उचेहरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

तभी से श्रद्धालु यहां माँ के दर्शन, पूजन और अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना के लिए पहुंचते हैं।

भक्तों की आस्था का केंद्र है माँ ज्वालाधाम

माँ ज्वालाधाम क्षेत्र की धार्मिक आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नवरात्रि सहित विभिन्न धार्मिक अवसरों पर यहां श्रद्धालु पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। धाम से जुड़ी लोककथा आज भी क्षेत्र की धार्मिक परंपरा को जीवंत बनाए हुए है।

21 अक्टूबर को होगा देवी जागरण, भक्तजन सपरिवार आमंत्रित

शारदेय नवरात्रि पर्व के अवसर पर माँ ज्वालाधाम शक्तिपीठ, उचेहरा में 21 अक्टूबर 2026, बुधवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर दोपहर 2 बजे से कलश स्थापना, जवारा जुलूस एवं विसर्जन कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं, रात्रि 8 बजे से देवी जागरण का विशेष आयोजन किया जाएगा।

देवी जागरण में कोतमा, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश के गायक ब्रज किशोर गुप्ता देवी भजनों की प्रस्तुति देंगे। इस दौरान श्रद्धालु माँ की भक्ति में लीन होकर भजनों का आनंद लेंगे और आध्यात्मिक वातावरण में सहभागी बनेंगे।

माँ ज्वालाधाम शक्तिपीठ, उचेहरा के संस्थापक एवं प्रधान पुजारी बड़े महाराज जी ने समस्त भक्तजनों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए धार्मिक कार्यक्रमों में सपरिवार सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से माँ ज्वाला के दरबार में उपस्थित होकर पूजा-अर्चना करने तथा देवी जागरण में सहभागिता निभाने की अपील की है।

जिले में चौथे स्तंभ पर हमला बर्दाश्त नहीं: पत्रकार को फोन पर गोली मारने की धमकी देने वाले माफियाओं पर शिकंजा, गाड़ी पकड़ी गई—एसपी शहडोल से कठोरतम कार्रवाई की पुरजोर मांग

हथगला में बदमाशों और रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, क्या कानून से ऊपर हो गए हैं अपराधी

शहडोल(अविरल गौतम)

शहडोल। जिले में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को डराने और दबाने के लिए अब अपराधी और माफिया सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। हाल ही में शहडोल जिले में सच दिखाने और अवैध गतिविधियों को उजागर करने वाले एक पत्रकार को फोन पर गोली से उड़ाने की धमकी देने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज घटना के बाद से स्थानीय पत्रकारों और आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

बड़ी कार्रवाई: धमकी देने वाले बदमाशों की गाड़ी पुलिस के कब्जे में सूत्रों और मिली जानकारी के अनुसार, पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और इस मामले से जुड़ी संदिग्ध/आरोपी गाड़ी को पकड़ लिया गया है।

वाहन के पकड़े जाने के बाद अब यह साफ हो गया है कि इस आपराधिक कृत्य में संलिप्त लोग बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे थे।

पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल से सख्त और निर्णायक कार्रवाई की मांग

शहडोल जिले के संवेदनशील एवं कड़क मिजाज पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के कार्यकाल में न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पत्रकारों और नागरिकों ने मांग की है कि इस मामले को सामान्य घटना न समझा जाए।

माफियाओं के नेटवर्क पर चले हथौड़ा: जिस तरह से बदमाशों ने एक पत्रकार को फोन पर गोली मारने की धमकी दी है, उससे साफ है कि इन्हें किसी का भय नहीं है। पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की गई है कि इस गाड़ी के मालिक और फोन पर धमकी देने वाले मुख्य षड्यंत्रकारियों (माफियाओं) को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।

कड़ी मिसाल कायम हो: आरोपियों के खिलाफ ऐसी कठोर कानूनी (रासुका या अन्य गंभीर धाराओं में) कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी सिरफिरा या अवैध कारोबारी कलम की ताकत को डराने की हिमाकत न कर सके।

'पत्रकारिता समाज का आईना है और सच की आवाज को गोलियों की धमकियों से दबाया नहीं जा सकता।

पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में शहडोल पुलिस से पूरी उम्मीद है कि वह इन अपराधियों को बेनकाब कर कानून का कड़ा पाठ पढ़ाएगी।

क्या पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुँचाने में कामयाब होगी इस पर पूरे जिले की नज़र टिकी हुई है।।

भाजपा मंडल का रुख:

अर्जुन सोनी (बुढार भाजपा मंडल) के अनुसार, पुलिस प्रशासन (एसडीओपी) को इस संबंध में कल ही सूचना दे दी गई थी।

कठोर कार्रवाई की मांग: अमलाई थाना क्षेत्र के ईटा भट्ठा के पास अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे वाहनों को पकड़ा गया है। इस पर पुलिस प्रशासन से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है।

आगे की चेतावनी:यदि अमलाई पुलिस या संबंधित प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करता है, तो भाजपा मंडल द्वारा इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक (एसपी) महोदय, शहडोल से की जाएगी।

पत्रकारों के समर्थन में संदेश: क्षेत्र के पत्रकारों को किसी भी प्रकार की धमकी देने या दबाव बनाने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे

संपादकीय

स्वतंत्र भारत में आंदोलनों की सार्थकता



15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था तो एक सपना था कि अब आंदोलनों का युग खत्म हुआ। अंग्रेज चले गए हैं, अब अपनी सरकार है, अब सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आजादी के अठहत्तर साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि स्वतंत्र भारत का असली इतिहास संसद में नहीं, सड़कों पर लिखा गया है। हर पीढ़ी ने अपने हिस्से का आंदोलन किया और उसी से लोकतंत्र जिंदा रहा।

संविधान में राज्यों का नक्शा अंग्रेजों के हिसाब से बना था। मद्रास प्रेसीडेंसी में तेलुगु भाषी अलग राज्य मांग रहे थे। पोट्टी श्रीरामुलु ने 58 दिन तक अनशन किया और जान दे दी। उनकी मौत ने पूरे दक्षिण को जगा दिया। नेहरू को झुकना पड़ा। इस तरह 1953 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने देश का नया नक्शा बनाया।

1974 में इंदिरा गांधी सत्ता में थीं तब बिहार के छात्रों के गुस्से को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति कहा। राममनोहर लोहिया ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस में कुर्सी का खेल चल रहा है, जाति और अंग्रेजी का राज है। जेपी ने उसी बात को सड़क पर उतार दिया। उनका कहना था कि यह केवल सरकार बदलने की लड़ाई नहीं, आदमी और व्यवस्था दोनों को बदलने की लड़ाई है। इंदिरा गांधी ने इस चुनौती का जवाब आपातकाल से दिया। पच्चीस जून 1975 को आधी रात को आपातकाल लगा दिया गया। एक लाख लोग बंद हुए, प्रेस पर सेंसर लगा। पर दमन ने आंदोलन को खत्म नहीं किया, बड़ा कर दिया। 1977 में जब चुनाव हुए तो आजाद भारत में पहली बार कांग्रेस हारी। लालू यादव, नीतीश कुमार, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसी पूरी पीढ़ी जेपी की पाठशाला से निकली।

अस्सी के दशक में उत्तराखंड के चमोली के रेणी गांव से उपजे चिपको आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहां ठेकेदारों को 2,400 से अधिक पेड़ काटने का ठेका मिला था। ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने पहुंचे तब गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे पर्यावरणविदों के नेतृत्व में यह आंदोलन फैला। बहुगुणा जी ने हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं कीं। तब इंदिरा गांधी को हिमालयी क्षेत्रों में 15 साल के लिए व्यावसायिक पेड़ कटाई पर रोक लगानी पड़ी। भारत में पर्यावरण संरक्षण की चेतना, वन संरक्षण कानून और पर्यावरण मंत्रालय के गठन के पीछे चिपको आंदोलन की अहम भूमिका रही।

इस आंदोलन की चेतना ने आगे चलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी प्रेरित किया। मेधा पाटकर और बाबा आमटे इस आंदोलन के मुख्य अगुवा थे। उनका संघर्ष इस बात के लिए था कि बांध से बिजली तो मिलेगी पर जिनके घर डूबेंगे उनका क्या होगा विस्थापन के सवाल पर दुनिया का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन चला। मेधा पाटकर अनेक बार अनशन पर बैठीं। आखिर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने पड़े कि बिना उचित पुनर्वास के बांध का काम आगे नहीं बढ़ेगा। भारत में पुनर्वास नीति की नींव यहीं से मजबूत हुई।

नब्बे का दशक आते-आते आंदोलन की धारा खेत और जंगल से निकलकर मंडल और कमंडल तक आ गई। मंडल कमीशन ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही। वीपी सिंह ने इसे लागू किया तो उत्तर भारत में व्यापक विरोध और प्रदर्शन हुए। सवर्ण छात्रों ने आत्मदाह तक किए। पर इस दौर ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जेपी आंदोलन और मंडल दौर से उभरे नेताओं ने सामाजिक न्याय और ओबीसी राजनीति को केंद्र में ला दिया। कांशीराम और मायावती भी उसी दौर की दलित और वंचित वर्गों की राजनीति से उभरे।

इसी समय राम जन्मभूमि आंदोलन ने दूसरा ध्रुव बनाया। लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा और बाबरी विध्वंस ने देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब धर्म और सांस्कृतिक पहचान राजनीति के केंद्र में आ गए। इसकी परिणति 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मति से आए फैसले और 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हुई।

नई सदी में आंदोलन का चेहरा बदला। वह किसान और मजदूर से निकलकर मध्यवर्ग के ड्राइंग रूम तक आ गया। 2011 में 2जी, कॉमनवेल्थ और कोयला घोटालों से आहत मध्यवर्ग अन्ना हजारे के साथ जंतर-मंतर पर बैठ गया। जनलोकपाल की मांग ने रामलीला मैदान को भर दिया। उसी के साथ 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड ने महिला सुरक्षा के सवाल को सड़क पर ला दिया। परिणामस्वरूप लोकपाल कानून बना, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और दुष्कर्म विरोधी कानूनों में भारी सख्ती आई।

सोशल मीडिया और मध्यवर्ग का यह गठजोड़ नया था। इसी नए दौर की अगली कड़ी ऐतिहासिक किसान आंदोलन था। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने व्यापक प्रदर्शन शुरू किया। 378 दिन तक सर्दी, गर्मी, बारिश और कोरोना के बीच यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चलता रहा। अंततः 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी।

और अब इसी परंपरा में नए आंदोलन भी जुड़ रहे हैं, जो छात्र अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े हैं।

सब का पानी एक, सब की हवा एक
सब का मालिक एक



साहबजादा अब्दुल रशीद खान
प्रधान सम्पादक सच्चे दिन समूह

आम आदमी की थाली पर महंगाई का सर्जिकल स्ट्राइक 2026



वैश्विक स्तरपर महंगाई जब केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित रहती है,थाली महंगी,बचत पर संकट और मध्यमवर्ग की बढ़ती बेचैनी,तब उसका प्रभाव बाजार की रिपोर्टों और सरकारी दस्तावेजों में दिखाई देता है,लेकिन जब वही महंगाई रसोई की चौखट पार करके आम आदमी की थाली, परिवार के मासिक बजट, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च और भविष्य की बचत पर चोट करने लगती है,तब वह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौती बन जाती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि भारत में14 अक्टूबर को सामने आए थोक मूल्य सूचकांक(डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर के 11.39 प्रतिशत तक पहुंचने के दावे, सितंबर 2026 की महंगाई से जुड़े आंकड़ों ने इसी गंभीर परिस्थिति की ओर संकेत किया है। इसके पूर्व 13 अक्टूबर को जारी खुदरा महंगाई के आंकड़ों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत पहुंचने और अभी थोक मूल्य सूचकांक ने आर्थिक बहस को तेज कर दिया है। यदि इन आंकड़ों की पुष्टि आधिकारिक मूल विज्ञप्तियों से होती है, तो यह स्थिति सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), उद्योग जगत और करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय होगी।सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रसोई का खर्च लगातार बढ़ने लगे, तो आम परिवार अपनी जरूरतों, इच्छाओं और बचत के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाए?

साथियों बात अगर हम रसोई के बजट पर महंगाई का सीधा हमला- इसको समझने की करें तो,शक्कर दालों से लेकर व प्याज से लेकर नींबू तक बढ़ती परेशानी भारतीय परिवारों के लिए रसोई केवल भोजन तैयार करने की जगह नहीं,बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दाल, चावल, आटा, प्याज, आलू, लहसुन,अदरक, नींबू और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का असर लगभग हर आय वर्ग पर पड़ता है।विशेष रूप से निम्न आय वर्ग और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खाद्य पदार्थों की महंगाई अधिक कष्टकारी होती है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च होता है। प्याज की कीमतों में असामान्य वृद्धि की खबरें, लहसुन और अदरक के महंगे होते भाव तथा नींबू जैसी सामान्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें घरेलू बजट को असंतुलित कर सकती हैं। शक्कर का खुदरा मूल्य 65 रुपये प्रति किलोग्राम बताए जाने का दावा भीउपभोक्ताओं की चिंता बढ़ाता है, हालांकि वास्तविक बाजार भाव शहर, गुणवत्ता और बिक्री केंद्र के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।महंगाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि परिवारों को समान आय में पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। कोई परिवार फल खरीदना कम करता है,कोई दूध और

पौष्टिक खाद्य पदार्थों की मात्रा घटाता है, तो कोई मनोरंजन, कपड़े और अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करता है। इस प्रकार महंगाई केवल जेब खाली नहीं करती, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और परिवार की आर्थिक सुरक्षा को भी सटीकता से प्रभावित करती है।

साथियों बात अगर हम खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत , थोक महंगाई 11.39 प्रतिशत- अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी? इसको समझने की करें तो, महंगाई के इन दोनों आंकड़ों को समझना आवश्यक है। खुदरा महंगाई बताती है कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितनी बदली हैं। दूसरी ओर, थोक महंगाई उत्पादकों और थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव का संकेत देती है।सरकारीआंकड़ों के अनुसार,सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54 प्रतिशत और थोक महंगाई बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई, जबकि अगस्त में ये क्रमशः4.83 प्रतिशत और 9.92 प्रतिशत थीं। खुदरा महंगाई के आधिकारिक आंकड़े 12 अक्टूबर को जारी हुए और थोक महंगाई के आंकड़े 14 अक्टूबर को सामने आए। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि 11.39 प्रतिशत थोक महंगाई का अर्थ यह नहीं है कि बाजार की प्रत्येक वस्तु 11.39 प्रतिशत महंगी हो गई है। इसका अर्थ है कि थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं के समग्र मूल्य स्तर में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इतनी वृद्धि दर्ज हुई है। फिर भी, थोक महंगाई का लगातार ऊंचा रहना चिंता बढ़ाता है, क्योंकि इससे कंपनियों की उत्पादन लागत, परिवहन खर्च और व्यापारिक गतिविधियों पर दबाव पड़ सकता है। यदि कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं, तो आने वाले महीनों में खुदरा बाजार में भी महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।

साथियों बात अगर हम ईंधन और कच्चे तेल का झटका- महंगाई की आग में घी इसको समझने की करें तोसितंबर के थोक महंगाई आंकड़ों में सबसे चिंताजनक पहलुओं में ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है। ईंधन एवं बिजली समूह की महंगाई अगस्त के 22.93 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 25.85 प्रतिशत पहुंच गई। प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई 8.67 प्रतिशत और विनिर्मित उत्पादों की महंगाई 9.76 प्रतिशत दर्ज की गई। थोक खाद्य सूचकांक भी अगस्त के 7.05 प्रतिशत से बढ़कर 8.66 प्रतिशत हो गया। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहता।माल ढुलाई महंगी होने से सब्जियों, अनाज और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने की लागत बढ़ सकती है। उद्योगों में बिजली, रसायन प्लास्टिक, पैकेजिंग और दूसरे कच्चे माल का खर्च भी बढ़ता है। यही कारण है कि ऊर्जा की महंगाई अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में एक साथ लागत का दबाव पैदा कर सकती है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और आपूर्ति संबंधी व्यवधान जारी रहते हैं, तो महंगाई पर नियंत्रण और कठिन हो सकता है।

साथियों बात अगर हम आर बीआई की अग्निपरीक्षा - ब्याज दरें बढ़ेंगी या आर्थिक विकास प्रभावित होगा?इसकोसमझने की करें तो, बढ़ती महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के सामने नीतिगत चुनौती खड़ी करती है। सितंबर में खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत तक पहुंचने से यह दर आरबीआई के 2 से 6 प्रतिशत के निर्धारित सहनशीलता दायरे की ऊपरी सीमा के अपेक्षाकृत करीब आ गई है। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय बैंक को महंगाई नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को गति देने के बीच संतुलन बनाना पड़ताहै।ब्याज दरें बढ़ाने से कर्ज महंगा हो सकता है और मांग पर दबाव पड़ सकता है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। गृह ऋण, वाहन ऋण और व्यावसायिक कर्ज की लागत बढ़ने से परिवारों और कारोबारियों का खर्च बढ़ सकता है। निवेश तथा उपभोग प्रभावित होने पर आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। इसलिए केवल रेपो दर में बदलाव से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति या मौसम के कारण पैदा हुई महंगाई का समाधान नहीं किया जा सकता। इसके लिए मौद्रिक नीति के साथ-साथ आपूर्ति प्रबंधन, बाजार निगरानी और समय पर सरकारी हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है।

साथियों बात अगर हम ग्रामीण परिवारों की चिंता और घटता आर्थिक भरोसा इसको समझने की करें तो, महंगाई का सबसे गहरा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ सकता है जिनकी आय सीमित है और जिनके पास अचानक बढ़े खर्चों से निपटने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है। ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वे के संदर्भ में प्रस्तुत आंकड़े भी इसी चिंता को सामने रखते हैं।

सांख्यिकीय उन्माद और खाली थालियाँ: 7 प्रतिशत वृद्धि के पीछे छिपी वास्तविकता की पुकार



अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने हाल ही में एक आशावादी रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने का दावा किया गया है। अब, जब आईएमएफ, विश्व बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ??वातानुकूलित कमरों में बैठकर भारत की विकास दर को 7 प्रतिशत या 7.1 प्रतिशत बताते हुए सुनहरे नारे लगा रही हैं, तो ये आंकड़े देश के आम नागरिक के लिए सांत्वना मात्र नहीं, बल्कि एक क्रूर मजाक हैं। एक ओर, वैश्विक संगठन दावा कर रहे हैं कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.1 प्रतिशत की धीमी गति से संघर्ष कर रही है, तब भारत एकमात्र चमकता हुआ इंजन बनकर उभर रहा है जो तेज गति से चल रहा है। भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था की धरती पर कदम रखते ही हमें एहसास होता है कि विकास की यह तेज रफ्तार केवल कागजों पर है। आम आदमी की जेब, उसके घरेलू बजट और उसकी रसोई की वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है और एक गंभीर आर्थिक संकट की ओर इशारा करती है। सांख्यिकीय भ्रम पैदा करके, देश के 1.4 अरब लोगों को इस भ्रम में रखा जा रहा है कि देश प्रगति कर रहा है, जबकि वास्तविकता में मध्यम और गरीब वर्ग उच्च मुद्रास्फीति, उच्च कीमतों और बेरोजगारी के तिहरे खतरे से कुचल रहा है।

सबसे पहले, आइए देश की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या यानी बेरोजगारी पर बात करते हैं। अगर हम ष्टस्द्बठ्ठश्च और सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखें, तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर लगातार 8 से 9 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, जो पिछले कुछ दशकों में सबसे अधिक है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि शिक्षित युवाओं और स्नातकों में बेरोजगारी दर 22 से 27 प्रतिशत तक पहुंच गई है। हर साल 12 लाख से अधिक युवा देश के श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में अच्छे रोजगारों का सृजन शून्य है। रेलवे, तलाटी या चपरासी के सिर्फ 100-200 पदों के लिए लाखों स्नातक और इंजीनियर कतार में खड़े हैं, आवेदन प्रक्रिया में वर्षों का समय लग गया है। देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा आज गुजारा करने के लिए फूड डिलीवरी बॉय, ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर बनने को मजबूर हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भारत की तथाकथित 7त्न विकास दर एक रोजगारविहीन विकास है।

दूसरी ओर, महंगाई दर और बढ़ती महंगाई के आंकड़े, जो आम नागरिक की कमर तोड़ रहे हैं, सरकार के दावों की पोल खोलते हैं। सितंबर में सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई बढ़कर लगभग 5.54त्न हो गई है, जो पिछले 4.83त्न से सीधी छलांग है। लेकिन सरकार द्वारा जारी की गई यह महंगाई दर आम गृहिणी की पीड़ा को नहीं माप सकती। रसोई में असली समस्या खाद्य महंगाई में छिपी है, जो वास्तव में 8.5त्न से 9.2त्न के स्तर तक पहुंच गई है। आम घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों में सालाना 35 से 45 प्रतिशत की चौंका देने वाली वृद्धि हुई है। प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन, अदरक और नींबू जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें बाजार में आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। दालों की कीमतों में सालाना 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खाद्य तेल की कीमतें एक बार फिर आम परिवारों की जेब पर भारी पड़ रही हैं।

ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि जब गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग को अपनी मासिक आय का 45 से 50 प्रतिशत हिस्सा केवल भोजन और अनाज पर खर्च करना पड़ता है, तो उनके लिए आर्थिक विकास का कोई मूल्य नहीं रह जाता। आम आदमी बाजार से जो कुछ भी खरीदकर रसोई में लाता है, वह सब बेहद महंगा होता है और उसका वजन या मात्रा पहले की तुलना में कम हो जाती है। आर्थिक दृष्टि से इसे %श्रिंकफ्लेशन% कहते हैं, जहां पैकेट की कीमत तो वही रहती है, लेकिन अंदर की सामग्री कम हो जाती है।

यह संकट केवल खाद्य पदार्थों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुद्रास्फीति ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव डाला है। देश में शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं में मुद्रास्फीति 11 से 14 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। साधारण सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की बिगड़ती स्थिति के कारण, मध्यम वर्ग निजी स्कूलों की अत्यधिक फीस और निजी क्लीनिकों के ऊंचे बिलों का भुगतान करने के लिए कर्ज में डूबता जा रहा है। आरबीआई की अपनी रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत ऐतिहासिक रूप से घटकर जीडीपी के 5.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई है, जो पिछले पांच दशकों में सबसे कम है। दूसरी ओर, आम परिवारों पर निजी ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण और स्वर्ण ऋण का अनुपात रिकॉर्ड गति से बढ़ रहा है। लोग अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने और त्योहार मनाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, जो एक गंभीर आर्थिक संकट की चेतावनी है।

वन में नवरात्रि- नर दिन में घूमकर अनुमति प्राप्त करते हैं ताकि मादाएं रात में घूम सकें

वन में नवरात्रि कभी माता की पूजा के लिए मनाई जाती थी। सभी जानवर, पक्षी, सरीसृप, समुद्री जीव और कीड़े-मकोड़े मिलकर माता की स्तुति करते थे। वे गरबा गाकर और खेलकर माता को प्रसन्न करते थे। गरबा खेलने की यह सांस्कृतिक परंपरा सदियों से वन में चली आ रही थी, लेकिन इसका मूल अर्थ था शक्ति के प्रति समर्पण। जिसे आज के आधुनिक वनवासी देसी गरबा या प्राचीन गरबा कहते हैं, वह विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता था। गायक और नर्तक कोई तमजाज नहीं करते थे। पुराने समय के गायकों में अपने गायन की मुद्राओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता नहीं थी।

गरबा खेलने में कोई विशेष खर्च नहीं होता था। कोई भी अपने पास मौजूद कपड़ों में गरबा खेल सकता था, और इसके अलावा, नवरात्रि वन के विभिन्न हिस्सों में सादगी से मनाई जाती थी, इसलिए उन दिनों बाहर जाकर कुछ खरीदने और खेलने का कोई विचार ही नहीं था। पुराने वनवासी पुराने तरीके से सोचते थे। उनमें व्यापारिक समझ नहीं थी। जब सैकड़ों वनवासी नवरात्रि में भाग ले रहे थे, तब वर्षों पहले वन में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दूरदर्शिता नहीं थी।

आधुनिक वनवासियों ने अपने पूर्वजों की अक्षमता की भरपाई कर ली है। आज के वनवासियों की दूरदर्शिता के चलते नवरात्रि का त्योहार अब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक अवसर बन गया है। पुराने वनवासियों द्वारा किसी भी पोशाक में गरबा खेलने की पुरानी और असुविधाजनक पद्धति को समाप्त करते हुए, आधुनिक वनवासियों ने विशेष प्रकार के पारंपरिक लेकिन आधुनिक परिधानों की व्यवस्था की है। गरबा में भाग लेने के लिए पारंपरिक कपड़े खरीदना आवश्यक है। इसी से डिज़ाइनर दर्ज़ियों का व्यवसाय पनपा। अगर आप खरीदना नहीं चाहते, तो आप उन्हें किराए पर भी ले सकते हैं। यहां तक ??कि कपड़े और सामान किराए पर देने वाली चकरी चकली भी अच्छी कमाई करती थी।

इसके अलावा, वन के सबसे धनी उद्योगपति गुलामदास गधेड़ा और उनके व्यापारिक साझेदार पप्पू पोपट का इस व्यवसाय पर एकाधिकार था। पप्पू पोपट ने गुलामदास के निवेश से वन में जगह-जगह रेस्तरां और कैफे बनवाए थे। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को तैयार होने में समय लगता था, इसलिए रसोई लगभग बंद रहती थी। जंगल कई मायनों में आधुनिक हो गया था, लेकिन रसोई को लेकर पुरुषों की सोच अभी भी पुरानी थी। ज्यादातर पुरुषों का मानना था कि खाना बनाना महिलाओं का काम है, इसलिए नवरात्रि के दौरान जब महिलाएं व्यस्त हो जाती थीं, तो उन्हें रसोई बंद करनी पड़ती थी। नतीजतन, पप्पू पोपट का खाने का कारोबार खूब फल-फूल रहा था। नवरात्रि के दौरान सबसे बड़ा कारोबार पार्टी प्लॉटों का होता था। इनमें पप्पू पोपट और गुलामदास गधेड़ा की जोड़ी का दबदबा था।

मुझे पीटा गया, मेरे बाल खींचे गए और मुझे घसीटा गया



राहुल गांधी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और शारीरिक दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्हें प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया, एक बस में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां उनकी पिटाई की गई। कुछ छात्रों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाया और उनका अपमान किया। राहुल गांधी ने छात्रों की बात सुनी और उनसे सबूत के तौर पर उनके पास मौजूद वीडियो पेश करने को कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला पेश करने वाली एक छात्रा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उससे कहा था कि दिल्ली पुलिस उसका पिता है। जब राहुल ने उससे पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है, तो छात्रा ने कहा कि शुरुआत में तो डर लगा था, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता।

दीपक ने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया- जनता पार्टी के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को जेल भेजने के बाद, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और कई अन्य नेताओं ने सरकार के इस कदम की आलोचना की। अभिजीत दीपक ने सभी नेताओं को धन्यवाद दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर से दिल्ली लौट रहे दीपक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को धन्यवाद दिया है। राहुल गांधी की पोस्ट पर दीपके ने लिखा, आशुतोष और सौरभ दास की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपका धन्यवाद, राहुल गांधी सर। एक वीडियो पोस्ट करते हुए दीपके ने एक और पोस्ट में लिखा, क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपराध है? सरकार भी तिरंगा फहराने को अपराध मानती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि अगर उनमें ताकत है तो उन्हें आपातकाल घोषित कर देना चाहिए।

राहुल गांधी के बाद ओवैसी ने भी मतदाता सूची के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है । एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में किए गए बदलावों को चुनौती दी है। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खर्गे और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने भी मतदाता सूची में किए गए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया की जांच के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट की मांग की थी। एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने की भी मांग की गई है। यह समिति मतदाता सूची और ईवीएम प्रणाली में किए गए बदलावों की भी जांच करेगी।

एकतरफा प्यार लंबे समय तक नहीं टिकता

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के कई नेता समय-समय पर पार्टी छोड़ते रहे हैं। एक के बाद एक कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद आनंद दुबे ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वे दुखी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मैंने पूरे मन, बुद्धि और धन से पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी द्वारा दी गई सभी जिम्मेदारियों को मैंने निभाया, लेकिन कुछ महीनों से मैं पार्टी की विचारधारा को नहीं भूल पा रहा हूं। उन्होंने कहा था, पार्टी में घुस आए तिलचट्टे, छिपकली, मक्खी और मच्छर जैसे कीड़े मेरे नेता नहीं हो सकते। सरजील इमाम, उमर खालिद, ध्रुव राठी जैसे नेता कभी मेरे नेता नहीं हो सकते। मेरे नेता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं।

इंदौर में 28 अक्टूबर को आयोजित होगा राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव



अर्बन चैलेंज फंड की 2,753.10 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मिलेगा नया आयाम

इन्दौर। मध्यप्रदेश में समृद्ध एवं आधुनिक नगरीय अधोसंरचना के सर्वांगीण विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा प्रदेश के शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने के ध्येय से आगामी 28 अक्टूबर, 2026 को इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख नगरीय विकास परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से जुड़े दूरगामी रणनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-मंथन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव प्रदेश के शहरी परिदृश्य को नई ऊँचाइयों पर ले जाने तथा नगरीय विकास की भावी दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अर्बन कॉन्क्लेव में 'अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों के साथ अनुबंध किये जाएँगे तथा संबंधित एजेंसियों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए जाएँगे ।

अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश के विभिन्न नगरों में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 2,753.10 करोड़ रूपये है। इस वित्तीय नियोजन के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और रीवा की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति दी जा रही है। इसके अंतर्गत इंदौर शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा सीवरेज नेटवर्क एवं उपचार संयंत्रों के व्यापक उन्नयन कार्य शामिल हैं। इसी श्रृंखला में धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में एकीकृत मंदिर क्षेत्र विकास की महत्वाकांक्षी परियोजना तथा रीवा नगर की सर्वसमावेशी जलप्रदाय योजना के कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है।

कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के अभूतपूर्व विस्तार, आधुनिक शहरी अधोसंरचना के निर्माण तथा वित्तीय संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग की संभावनाओं को नए आयाम दिए जा रहे हैं। अर्बन चैलेंज फंड से संचालित ये परियोजनाएं न केवल शहरों में जन-सुविधाओं का विस्तार कर ईज़ ऑफ लिविंग के उच्च मानक स्थापित करेंगी, बल्कि नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाते हुए क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी संबल प्रदान करेंगी।

राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव शहरी विकास के क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रमुख निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, नवोन्मेषी स्टार्टअप्स तथा ऊर्जावान युवाओं को मध्यप्रदेश में सृजित हो रही अपार विकास संभावनाओं से सीधे जुड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। कॉन्क्लेव में सहभागिता के इच्छुक निवेशक, स्टार्टअप्स एवं युवा आधिकारिक वेब पोर्टल ugconclave.mp.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल से मध्यप्रदेश के शहरों में सतत, समावेशी एवं आधुनिक विकास का नया अध्याय प्रारंभ होगा।

राज्य शासन का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय

इन्दौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप राज्य शासन ने मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए सीपीसीटी में छूट आदि से संबंधित समेकित निर्देश जारी किया है। अब जहां सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति के लिए 45 वर्ष से अधिक के कर्मियों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड से पूरी छूट दी है वहां अन्य पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद निर्धारित कम्प्यूटर अर्हताएं प्राप्त करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष का अवसर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत सभी विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आ रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की अनिवार्यता के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए हैं।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को ष्टक्कष्टञ्ज स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है। साथ ही अन्य पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद निर्धारित कम्प्यूटर अर्हताएं प्राप्त करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष का अवसर दिया गया है। अब सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्हें ष्टक्कष्टञ्ज एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है, उन्हें पदोन्नति के बाद 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में ष्टक्कष्टञ्ज परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा अथवा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करना होगी।

यदि कर्मचारी 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में आवश्यक अर्हताएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनकी परिवीक्षा अवधि अधिकतम 3 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी। इस प्रकार उन्हें पदोन्नति के बाद कुल 5 वर्ष के भीतर निर्धारित योग्यता प्राप्त करनी होगी। इस अवधि में आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी को उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस पदस्थ कर दिया जाएगा।उक्त प्रावधान केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होंगे।

सीधी भर्ती अथवा अन्य किसी माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में ष्टक्कष्टञ्ज एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की निर्धारित अर्हताएं यथावत अनिवार्य रहेंगी।

आदेश अनुसार शासकीय सेवक अपनी पदोन्नति की तिथि को 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें सहायक ग्रेड-3 पर पदोन्नति हेतु ष्टक्कष्टञ्ज स्कोर कार्ड से छूट प्रदान की गई है, परंतु कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगी।

एमपी ट्रांसको में महिला इंजीनियरों के साथ अब दिव्यांग इंजीनियरों की भी तकनीकी और मैदानी कार्यों में भागीदारी



इन्दौर। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) में महिला इंजीनियरों की तरह अब दिव्यांग इंजीनियर भी तकनीकी और मैदानी कार्यों में अपने सहकर्मियों के साथ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इंदौर के मालवा क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइनों के मेंटेनेंस से लेकर एक्स्ट्रा हाई टेंशन (ईएचटी) सबस्टेशनों की टेस्टिंग और रखरखाव तक महिला अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी क्रम में बीना में दिव्यांग इंजीनियर भी पावर ट्रांसफार्मर के परीक्षण और रखरखाव सहित नियमित तकनीकी कार्यों में भागीदारी कर रहे हैं।

इंदौर में महिला इंजीनियर संभाल रहीं मेंटेनेंस जिम्मेदारियां-एमपी ट्रांसको की अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रीमती नीलम खन्ना मालवा क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइनों के मेंटेनेंस का कार्य देखती हैं। उनके साथ कार्यपालन अभियंता श्रीमती नम्रता जैन ने पिछले वर्ष इंदौर शहर में त्योहारों के दौरान निर्बाध विद्युत पारेषण व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सुबह और रात के समय शटडाउन लेकर लाइन संबंधी कार्य कराए थे, ताकि त्योहारों के दौरान विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर अनावश्यक असर न पड़े।

इंदौर के एक्स्ट्रा हाई टेंशन सबस्टेशनों में टेस्टिंग और मेंटेनेंस संबंधी कार्यों में श्रीमती विनीता भावसार और श्रीमती नूतन शर्मा सहित अन्य महिला अभियंता भी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इन कार्यों में तकनीकी परीक्षण, उपकरणों के रखरखाव और पारेषण व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने से जुड़े दायित्व शामिल हैं।

बीना में दिव्यांग इंजीनियर भी कर रहे ट्रांसफार्मर टेस्टिंग और मेंटेनेंस- बीना स्थित 220 केवी सबस्टेशन में 200 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर के मानसून-पश्चात रखरखाव कार्य में दो दिव्यांग इंजीनियरों ने अपने सहकर्मियों के साथ भागीदारी की। 400 केवी टेस्टिंग डिवीजन, बीना में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी ऋषिकांत सेन, जिनका दाहिना हाथ नहीं है, और जूनियर इंजीनियर ट्रेनी शुभम श्रीवास्तव रखरखाव एवं परीक्षण संबंधी कार्यों में तकनीकी भूमिका निभा रहे हैं।

कार्यपालन अभियंता अर्चित श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में दोनों इंजीनियर ट्रांसफार्मर की जांच, परीक्षण और रखरखाव सहित डिवीजन के नियमित, निवारक तथा ब्रेकडाउन संबंधी कार्यों में भाग लेते हैं। सहायक अभियंता रजत जैन भी उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देने और कार्यों में सहयोग करने की भूमिका निभा रहे हैं।

अन्य विभागों में भी दिव्यांग अधिकारी निभा रहे दायित्व- एमपी ट्रांसको के प्रोक्योरमेंट विभाग में कार्यपालन अभियंता विकास श्रीवास्तव, टेस्टिंग डिवीजन टीकमगढ़ में सहायक अभियंता जी.पी. राय तथा अकाउंट्स ऑफिसर नेहा गुप्ता सहित अन्य दिव्यांग अधिकारी भी अपने-अपने विभागों में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

इस तरह कंपनी में महिला इंजीनियरों की तकनीकी और मैदानी कार्यों में भागीदारी के साथ दिव्यांग इंजीनियरों की सहभागिता भी ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस, सबस्टेशन टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर रखरखाव और अन्य विभागीय कार्यों में सामने आ रही है।

बेसमेंट में रेस्टोरेंट, किचन और कोचिंग पर बैन, एमपी में लागू हुए नए फायर सेफ्टी रूल्स



इंदौर। मध्य प्रदेश में बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी रूल्स को लेकर बड़ी सख्ती की गई है। मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम-2026 में अब नियमों को तोड़ने पर एफआईआर के साथ बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इमारतों में जांच के बाद कमियों को दूर करने के लिए केवल 30 दिन का ही समय दिया जाएगा। नए नियमों के तहत अधिकारियों की ओर से होने वाली कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कमियां दूर न करने पर इमारत या भवन को असुरक्षित घोषित कर सील कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई सील तोड़कर बिना किसी एनओसी के फिर से इमारत में अपना काम जारी रखता है तो उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं ऐसे मामले में बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बेसमेंट में किचन और बैटरी रखने पर भी पांबदी- नए नियमों के तहत इमारतों के बेसमेंट में किसी भी तरह के व्यावासायिक गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। यहां किचन, रेस्टोरेंट, रूम, हॉस्टल नहीं बनेंगे। इसके साथ ही बेसमेंट में ज्वलनशील पदार्थ और बैटरी और यूपीएस भी नहीं रखा जा सकेगा। अधिकारी समय-समय पर इसको लेकर इमारतों की जांच करेंगे। अगर नियमों का उल्लंघन मिलता है तो तुरंत कार्रवाई होगी।

पेट्रोल-डीजल और ईवी के लिए सेंसर- बेसमेंट में ईलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग और पार्किंग के लिए रेट ऑफ राइज हीट सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही जहां बेसमेंट में पेट्रोल-डीजल वाहन पार्क होते हैं वहां कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर लगाना होगा। इससे धुआं उठने या जहरीली गैस बेसमेंट में होने की स्थिति में सेंसर तुरंत अलट करेगा।

बड़ी इमारतों और अस्पताल में अलर्ट पर रहेगा अमला- नए फायर सेफ्टी रूल्स के अनुसार बड़ी इमारतों और 100 से ज्यादा बिस्तर वाले अस्पतालों सहित बड़ी होटलों और मॉल में फायर सेफ्टी अमले को 24 घंटे अलर्ट पर रहना होगा। ताकि आग लगने की स्थिति में वे तुरंत रिस्पांस कर उस पर काबू पा सकें।

बड़ी आग लगने की स्थिति में सरकार अब किसी भी निजी वाहन को अधिग्रहित कर सकेगी। जिससे पानी के टैंकरों सहित अन्य वाहनों के जरिए आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। अगर कोई इमरजेंसी के दौरान अपना वाहन सरकार को नहीं देता है तो इसे अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही फायर सेफ्टी को लेकर फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

त्योहारों पर इंदौर-जोधपुर और इंदौर-भगत की कोठी एक्सप्रेस सहित तीन जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगेंगे, यात्रियों को मिलेगी सुविधा



इंदौर। दुर्गा पूजा, दीपावली सहित आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं अतिरिक्त यात्री दबाव को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली दो जोड़ी ट्रेनों में अस्थाई रूप से अतिरिक्त कोच लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे त्योहारों पर यात्रियों के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं सफर करने वालों को सुविधा होगी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस में 16 से 31 अक्टूबर तक व इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस में 19 अक्टूबर से तीन नवंबर तक दो स्लीपर श्रेणी एवं तीन जनरल श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। वहीं, इंदौर-भगत की कोठी एक्सप्रेस में 17 अक्टूबर से एक नवंबर तक व भगत की कोठी-इंदौर एक्सप्रेस में 18 अक्टूबर से दो नवंबर तक दो स्लीपर श्रेणी एवं तीन जनरल श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। त्योहारों पर यात्री दबाव देखते हुए रेल मंडल से गुजरने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन 19625/19626 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस में 18 से 25 अक्टूबर तक एक स्लीपर कोच लगेगा। ट्रेन 14801/14802 जोधपुर-इंदौर में निर्धारित अवधि में दो स्लीपर और तीन जनरल कोच तथा ट्रेन 12465/12466 इंदौर-भगत की कोठी में भी दो स्लीपर और तीन जनरल कोच लगाए जाएंगे। यात्रियों से यात्रा से पहले समय, ठहराव और ट्रेन की स्थिति www.enquiry.indianrail.gov.in या RailOne एप पर जांचने की अपील की गई है।

अतिरिक्त कोच की अवधि

19625 अजमेरङ्कबांद्रा टर्मिनसः 18- 25 अक्टूबर, 19626 वापसीः 19- 25 अक्टूबर, एक स्लीपर कोच।

14801 जोधपुरङ्कइंदौरः 16ङ्क31 अक्टूबर, 14802 वापसी ः 19 अक्टूबरङ्क तीन नवंबर, दो स्लीपर और तीन जनरल कोच।

- 12465 इंदौरङ्कभगत की कोठीः 17 अक्टूबरङ्क एक नवंबर, 12466 वापसी ः 18 अक्टूबरङ्क दो नवंबर, दो स्लीपर और तीन जनरल कोच।

इंदौर के सुशीला देवी बंसल कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



इन्दौर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा युवाओं में सुरक्षित यातायात व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से आदर्श सड़क सुरक्षा नगर परियोजना के अंतर्गत इंदौर स्थित के सुशीला देवी बंसल कॉलेज, में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एशियन रोड सेफ्टी एकेडमी एवं होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग इंदौर के निर्देशन में किया गया।

कार्यक्रम में डॉ. प्रेरणा अरोड़ा सिंह ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए सुरक्षित दोपहिया वाहन चालन के सही तरीकों और सड़क पर जिम्मेदार व्यवहार के महत्व को समझाया।

उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करने के साथ-साथ संभावित खतरों को समय रहते पहचानना और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सही निर्णय लेना भी आवश्यक है। वीडियो के माध्यम से समझाए गए सड़क पर संभावित खतरे कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से सड़क पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न खतरनाक परिस्थितियों को प्रदर्शित किया गया। डॉ. प्रेरणा अरोड़ा सिंह ने विद्यार्थियों को समझाया कि अचानक सामने आने वाले वाहन, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की अप्रत्याशित गतिविधियां तथा यातायात परिस्थितियों में अचानक होने वाले बदलाव दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सतर्क रहना, गति नियंत्रित करना और सुरक्षित तरीके से प्रतिक्रिया देना अत्यंत आवश्यक है।

कार्यक्रम में डॉ. प्रेरणा अरोड़ा सिंह ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों पर जोर दिया। उन्?होंने कहा कि आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी रखने से अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में टक्कर से बचने में मदद मिलती है। सड़क, यातायात और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार उचित गति बनाए रखना तथा संभावित खतरे को देखते ही गति कम करना आवश्यक है। चारपहिया वाहन में चालक और सभी यात्रियों को सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। साथ ही सड़क पर संभावित जोखिमों को पहले से पहचानना, सतर्क रहना और समय पर उचित निर्णय लेना सुरक्षित वाहन चालन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने विद्यार्थियों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने और सड़क पर अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उन्हें दैनिक जीवन में सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना भी था। युवाओं में विकसित होने वाली सुरक्षित ड्राइविंग आदतें न केवल उनके अपने जीवन की रक्षा करती हैं, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

राज्य शासन ने पैराक्वेट डाइक्लोराइड के उपयोग पर लगाया प्रतिबन्ध

इन्दौर। राज्य शासन ने पैराक्वेट डाइक्लोराइड नामक कीटनाशक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कीटनाशक मानव और पशुओं के लिए बेहद हानिकारक है। भारत सरकार ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है।

किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने इस खतरनाक कीटनाशक का निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा विक्रय और भण्डारण पर तत्काल रोक लगाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिन निर्माताओं के पास पैराक्वेट डायक्लोराइड के पंजीकरण प्रमाण पत्र है उन्हें तत्काल केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति को वापस करने के निर्देश दिए हैं। इस कीटनाशक के बचे स्टाक को वापस बुलाकर नियम, प्रक्रिया अनुसार नष्ट करने की कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत पैराक्वेट डाइक्लोराइड के नए रजिस्ट्रेशन और पहले से जारी सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को रद्द कर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के लगभग 70 देशों में इसका उपयोग पहले से प्रतिबंधित है।

कैसे काम करता है- यह पौधों के हरे हिस्सों के संपर्क में आते ही उन्हें तेजी से जलाकर नष्ट कर देता था। इसे ग्रामोक्सोन जैसे ट्रेड नाम से भी जाना जाता है। यह इंसानों और जानवरों के लिए अत्यधिक विषैला है। इसके शरीर में जाने या संपर्क में आने से फेफड़े और गुर्दे (किडनी) गंभीर रूप से खराब हो जाते हैं। इसका कोई विशिष्ट एंटीडोट (विषारोधी इलाज) उपलब्ध नहीं है। किसान मूंग की फसल में पैराक्वेट डाइक्लोराइड का उपयोग फसल की कटाई से ठीक पहले पत्तियों को सुखाने और फसल को जल्दी पकाने के लिए करते हैं। इसका छिड़काव करने से मूंग के हरे पौधे और पत्तियां 24 से 72 घंटों के भीतर पूरी तरह सूख जाती हैं। पत्तियां सूख जाने से फसल को काटना और थ्रेसिंग करना आसान हो जाता है, जिससे मजदूरों का खर्च और समय बचता है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार इसका उपयोग मूंग की फसल पर करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद किसान अवैध रूप से इसका शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल के सिद्धांत सिंह का संभाग स्तरीय चयन



सीधी। जिले के साउथ जोगीपुर स्थित ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र सिद्धांत सिंह का बालक वर्ग अंडर-14 संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता 16 एवं 17 अक्टूबर को सीधी में आयोजित होगी। सिद्धांत सिंह के चयन से विद्यालय परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है। छात्र की इस उपलब्धि में उनके परिश्रमए लगन और खेल के प्रति समर्पण के साथ-साथ कोच पुष्पराज सिंह सोलंकी के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोच ने छात्र को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। विद्यालय प्रधानाचार्य निवेदिता चटर्जी, उप प्रधानाचार्य संजय त्रिपाठी एवं सभी शिक्षकों ने सिद्धांत सिंह को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएँ दीं। विद्यालय परिवार को विश्वास है कि सिद्धांत सिंह अपने खेल कौशल से विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। विद्यालय प्रबंधन धरम विजय परिहार ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की उपलब्धियाँ अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों में आगे बढने और अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित करती हैं। सिद्धांत सिंह की इस सफलता पर समस्त स्कूल परिवार ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं।

बस स्टैंड हटना बेहद है जरूरी-पंकज



सीधी। भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष एड. पंकज पाण्डेय ने कहा कि पुराना बस स्टैंड हटना बेहद जरूरी है कारण यह कि वहां काफी आबादी हो गई है। करीब एक लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है जिस वजह से आवागवन में परेशानी है। नए बस स्टैंड की दूरी करीब 1 किलोमीटर है जहां किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है न किसी का रोजगार छिनेगा। उन्हें उचित स्थान भी दिलाने के लिए सीधी विधायक रीती पाठक ने संकल्प ली हैं फिर भी सीधी के पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला राजनीति कर रहे हैं। उनका काम ही यह है रीती पाठक अच्छा काम कर रही हैं विकाश के लिए वह संकल्पित हैं।

अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर न्यायालय का सख्त आदेश

सीधी। जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में कलेक्टर विकास मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। सीधी खुर्द स्थित तीन अलग-अलग भूमियों पर बिना वैध अनुमति प्लॉटिंग किए जाने के मामलों में कलेक्टर न्यायालय ने कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए संबंधित भूमियों पर भू-प्रवेश की कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त करने और जिम्मेदारों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेशों के अनुसार, ग्राम सीधी खुर्द स्थित खसरा नंबर 303 की 0.2430 हेक्टेयर, खसरा नंबर 157/5/1/1 की 0.0854 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 156/2/1/1 की 0.2799 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है। इन भूमियों पर क्रमशः नौ, दो और छह भूखंडों के विक्रय का उल्लेख आदेशों में किया गया है।

[अपराध] कई वर्षों से कन्वर्जन को लेकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर दिया जा रहा था प्रलोभन

धर्मांतरण के मामले में दोषी मां-बेटी पहुंची जेल

सीधी (नि.प्र.)



जिले में धर्मांतरण के मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें मां-बेटी को जेल की हवा अब खानी पड़ेगी। जमोड़ी थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया इसके बाद न्यायालय ने जेल भेज दिया गया है।

फरियादी ने आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन के बदले एक लाख रुपये, सरकारी नौकरी और मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रलोभन दिया जा रहा था। मामला 12 अक्टूबर 2026 को उस वक्त चर्चा में आया, जब एमपीईबी सीधी कॉलोनी के पीछे एक निजी मकान में आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान विवाद और मारपीट की घटना सामने आई थी। एमपीईबी कॉलोनी के पीछे स्थित एक निजी मकान में आयोजित प्रार्थना सभा को लेकर विवाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक 12 अक्टूबर को प्रार्थना सभा की सूचना मिलने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। यहां कथित धर्मांतरण की गतिविधियों को लेकर विवाद हुआ और मारपीट की घटना सामने आई। इस दौरान तीन कार्यकर्ताओं के घायल होने की जानकारी भी मिली थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।

थाने में दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट

इस पूरे मामले में फरियादी रघुनाथ प्रजापति ने 12 अक्टूबर 2026 को जमोड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी का आरोप था कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके बदले एक लाख रुपये देने की बात कही गई। इतना ही नहीं, अन्य लोगों को जोडऩे पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लाख रुपये, सरकारी नौकरी और मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रलोभन दिए जाने का भी आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में फरियादी ने कहा है कि इस दौरान उससे कहा गया था कि भगवान ईशा मशीह के मार्ग पर चलना होगा। अपने हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानोगे तथा उनकी जो फोटो घर में होगी उनको फेंक देना। हांथ में कोई भी धागा नहीं पहनोगे। इस दौरान बाइबिल की कहानियां व बाइबिल नया नियम की पुस्तकें तथा 3 हजार रुपए दिए गए थे। जिसमें 2 हजार रुपए खर्च हो गया और 1 हजार रुपए बचा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नीलम दीक्षित और गीता दीक्षित दोनो निवासी मेघदूत पार्क के पीछे सीधी को गिरफ्तार किया।

इनका कहना है



पुलिस ने दोनों महिलाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत कार्रवाई की। इसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। हालांकि, धर्मांतरण और प्रलोभन से जुड़े आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

राघवेंद्र द्विवेदी, डीएसपी मुख्यालय सीधी

धर्मांतरण के मामले में जो शिकायतें आई थी उसमें पुलिस ने एक्शन में लेकर कार्रवाई की है। इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसका संदेश भी देना चाहते हैं। हर लोग अपने समाज में सुखमय जीवन व्यतीत करें।

संतोष कोरी, एसपी सीधी

तत्काल कार्रवाई का दिया गया फरमान

इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. अशोक खरे ने कहा कि इस मामले में संबंधित स्टाफ नर्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि अभी मैं मीटिंग में हूं फिर भी जल्द ही ऐसे स्टाफ नर्स पर कार्रवाई होगी।

सिंगरौली में लोकायुक्त ने की कार्यवाही

रिश्वत लेते जल संसाधन का बड़ा बाबू ट्रैप



सीधी (नि.प्र.)



जल संसाधन विभाग के कार्यालय में लोकायुक्त टीम की भनक लगते ही वहां हड़कंप मच गया। लोकायुक्त पुलिस ने कथित तौर पर विभाग में पदस्थ बड़े बाबू को रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जाता है कि आरोपी बड़ा बाबू ने एक व्यक्ति को बीमा राशि दिलवाने के एवज चार हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगरौली जल संसाधन विभाग में पदस्थ बड़े बाबू दिनेश कुमार श्रीवास्तव को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरोप है कि शिकायतकर्ता रंजन साकेत नामक व्यक्ति से बीमा राशि निकलवाने की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। कार्रवाई के बाद विभाग की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के आचरण और उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

विभा शर्मा बनीं भाजपा सोशल मीडिया जिला संयोजक



सीधी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के निर्देशानुसार एवं सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक सुयश त्यागी की सहमति से भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एवं एल्डरमैन श्रीमती विभा शर्मा को सोशल मीडिया का जिला संयोजक नियुक्त किया है। नवनियुक्त जिला संयोजक श्रीमती शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर पार्टी की सोशल मीडिया गतिविधियों के समन्वय, संगठनात्मक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार तथा पार्टी की नीतियों, विचारों और जनहित से जुड़े कार्यों को डिजिटल माध्यमों के जरिए आमजन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी। सोशल मीडिया वर्तमान समय में संगठन और आमजन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में जिला संयोजक के रूप में विभा शर्मा की भूमिका पार्टी की डिजिटल गतिविधियों के संचालन एवं संगठनात्मक संदेशों के प्रभावी प्रसार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी।

स्वाती का म.प्र. वॉलीबॉल टीम में चयन

■ अब राजस्थान में दिखाएगी दम

सीधी (नि.प्र.)



जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के गोनर्रा गांव की स्वाती वैश्य केवल 15 वर्ष की उम्र में जिले के लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर स्वाती ने राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में जगह बनाई है। आगामी 22 अक्टूबर 2026 को राजस्थान में आयोजित होने वाले नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में स्वाती अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी।स्वाती के पिता विनोद वैश्य, भाजपा गोरबी मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि स्वाती ने लगातार चार वर्ष तक कड़ा अभ्यास कर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलते हुए अपनी प्रतिभा साबित की। इसके बाद उनका चयन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में हुआ है।

माता-पिता के सहयोग से निखरी प्रतिभा

राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपने चयन से स्वाती और उनका पूरा परिवार बहुत खुश है। स्वाती ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता-पिता को दिया है। उसका कहना है कि पिछले चार वर्षों से लगातार अभ्यास करने का परिणाम आज सामने आया है। इस दौरान माता-पिता का सहयोग और प्रोत्साहन हमेशा उनके साथ रहा। उनके समर्थन और अपनी मेहनत के बल पर ही राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिला है।

नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित, सिविक सेंटर निर्माण को मिली मंजूरी

सीधी (नि.प्र.)



नगर पालिक निगम सिंगरौली की परिषद की साधारण बैठक नगर निगम अध्यक्ष श्री देवेश पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर के समग्र विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाने तथा नगरीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहरवासियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सिविक सेंटर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई।

इसके साथ ही स्टोर में रखी पुरानी अनुपयोगी सामग्री की नीलामी, मल्हार पार्क में अग्रसेन महाराज की प्रतिमा स्थापित करने तथा जयंत अस्पताल के समीप स्थित तिराहे का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर करने के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। बैठक में सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामनिवास शाह, महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल, मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य खुर्शीद आलम, श्रीमती शिवकुमारी कुशवाहा, श्रीमती रुकमुन प्रजापति, श्रीमती श्यामा वर्मा, श्रीमती बबली शाह एवं श्रीमती अंजना शाह सहित नगर निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान उपस्थित रहीं। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रगान के गायन के साथ हुआ।

शासकीय जमीन में सरपंच का बेजा कब्जा, ग्रामीणों में आक्रोश

■ मामला ग्राम पंचायत बोदारी टोला का

सीधी (नि.प्र.)

जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदारी टोला के सरपंच राम शिरोमणि यादव के द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय के बगल में वेसकीमती शासकीय जमीन जो सार्वजनिक निस्तार में रहती थी उसमें अपने पद और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पहले अपने भाई का घर बनवाया फिर खुद शेष जमीन में अपना घर बना रहा है और बेजा कब्जा कर लिया है जिससे ग्रामीणों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है।

ग्रामीणों के मुताबिक जिस जमीन में ग्राम पंचायत का कार्यालय बना है वह मध्य प्रदेश शासन की जमीन है जिसमें ग्राम पंचायत कार्यालय का निर्माण किया गया था एवं शेष जमीन आम निस्तार में पड़ी थी जिस पर सरपंच की निगाह पहले से ही पड़ी थी और जैसे ही सरपंच निर्वाचित हुआ तो उसे अपनी पैतृक जमीन मानकर पहले खेती के लिए कब्जा किया फिर आधा-आधा हिस्सा बांट कर आधे जमीन में पहले अपने भाई का मकान उसी जमीन में बनवाकर कब्जा करवाया एवं आधी जमीन में खुद अपना घर बना कर कब्जा कर रहा है।



इनका कहना है

ग्राम पंचायत के बगल में शासकीय जमीन थी जिसमें पहले सरपंच राम शिरोमणि यादव के भाई का घर बनाया गया है फिर खुद सरपंच घर बना रहे हैं।

सावित्री यादव ग्रामीण

ग्राम पंचायत के बगल में जो घर बन रहा है वह सरपंच का है एवं उसके बगल में उनके भाई का बना है।

राम शिरोमणि यादव सरपंच

ग्रामीणों की शिकायत पर मेरे द्वारा जांच कराई गई है जिसमें शासकीय जमीन में बेजा कब्जा करना पाया गया है जिस कारण बेदखली का प्रकरण चलाया गया है जल्द ही उस जमीन से कब्जा हटाया जाएगा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

दिलीप सिंह तहसीलदार मझौली

एनटीपीसी विंध्याचल में रंगों से सजा डांडिया व गरबा उत्सव

सीधी (नि.प्र.)



एनटीपीसी विंध्याचल में मूल मूल्य परस्पर सम्मान एवं विश्वास के अंतर्गत नवरात्रि गतिविधियों की श्रृंखला में 14 अक्टूबर 2026 को वीवा प्रांगण में डांडिया म्यूजिकल चेयर एवं गरबा फ्रीस्टाइल डांस का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कर्मचारियों की जीवनसंगिनियों, महिला आश्रितों एवं बच्चों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और संगीत, नृत्य एवं मनोरंजक गतिविधियों का भरपूर आनंद उठाया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अक्टूबर माह के कोर वैल्यू ÷परस्पर सम्मान एवं विश्वास÷ चैंपियन प्रणव वर्मा, अपर महाप्रबंधक(मानव संसाधन) के उद्घाटन संबोधन से हुआ। इस अवसर पर 'परस्पर सम्मान एवं विश्वास' की पूरी मूल मूल्य टीम तथा वीवा के महासचिव हिमांशु कैतवास उपस्थित रहे। उल्लास एवं सहभागिता से भरपूर इस आयोजन ने कर्मचारियों के परिवारों को एक साथ जोड़ते हुए आपसी सम्मान, विश्वास एवं सौहार्द की भावना को सुदृढ़ किया।

एनसीएल एक्सप्रेस वे पर कोल वाहनों का कब्जा, चरमराई यातायात व्यवस्था

सीधी (नि.प्र.)



कोयला परिवहन एवं नागरिक वाहनों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग लेन में बनाए गए एनसीएल एक्सप्रेसवे के दोनों लेनों पर अब भारी कोल वाहनों ने कब्जा कर लिया है जिससे आम नागरिकों का आवागमन मुश्किल और जानलेवा होता जा रहा है। सिंगरौली से जयंत और बैढ़न के बीच आने जाने वाले लोगों को जान हथेली पर लेकर भारी कोयला वाहनों के बीच से निकालने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति ने पुलिस सहित जिला प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि सब-स्टेशन के आसपास की स्थिति अधिक परेशानी पैदा कर रही है। खदान की ओर जाने वाले ट्रेलर और हाइवा के सड़क पर कतारबद्ध होने से आवागमन प्रभावित होता है। भारी वाहनों के जमावड़े के बीच छोटे वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। सबसे गंभीर स्थिति तब बन सकती है, जब जाम में एंबुलेंस या किसी मरीज को ले जा रहा वाहन फंस जाए।

ऐसे में समय पर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। ऊर्जा के लिए कोयला उत्पादन और परिवहन महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इस अंचल में रहने वाले लाखों लोगों का एनसीएल और देश के लिए कोई महत्व नहीं है। औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के साथ सार्वजनिक मार्गों पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित रखना भी एनसीएल के साथ साथ शासन प्रशासन के लिए जरूरी है।

मां धनौजा मंदिर में आयोजित शास्त्रीय गरबा महोत्सव में जुटे श्रद्धालुओं ने रचा नया इतिहास

सीधी (नि.प्र.)

शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि, बुधवार की शाम सरई क्षेत्र का पौराणिक धनौजा मंदिर प्रांगण भक्ति, उमंग और सांस्कृतिक उल्लास का केंद्र बन गया था। अवसर था शास्त्रीय गरबा महोत्सव का। इसका संयोजन पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत घोघरा श्रीमती सुगंन कंवर सिंह भाटी ने किया था। कार्यक्रम भव्य था तथा उसके आकर्षण से हजारों की संख्या में लोग दूर-दराज़ के गाँवों से पहुँचे और इस सांस्कृतिक उत्सव के साक्षी बने। ढोल-नगाड़ों की थाप और संगीत की धुनों पर महिलाओं और बच्चियों ने पारंपरिक परिधानों में गरबा नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। नृत्य की लय और रंग-बिरंगी डांडियों की खनक ने वातावरण को और भी दैवीय बना दिया। रात 12 बजे तक चले इस आयोजन में हर वर्ग के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और सांस्कृतिक धारा में डूबते-उतराते रहे।

उल्लेखनीय है कि सरई क्षेत्र में गरबा महोत्सव की परंपरा की शुरुआत प्रेम सिंह भाटी ने की थी। उनके प्रयासों और निरंतर सामाजिक सक्रियता का ही परिणाम है कि आज सरई क्षेत्र के कोने-कोने में गरबा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है।उनके द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों ने न केवल स्थानीय संस्कृति को नई पहचान दी, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं से जुड़ने की प्रेरणा दी है। इन दिनों सम्पूर्ण सरई क्षेत्र में गरबा महोत्सव की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। नगर के कोने-कोने में आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों के मूल प्रेरणास्रोत समाजसेवी प्रेम सिंह भाटी की पत्नी सुगंन कंवर सिंह भाटी ही मानी जा रही हैं। वर्ष 2024 में सर्वप्रथम माँ धनौजा मंदिर प्रांगण में उनके प्रयासों से गरबा का आयोजन हुआ, जिसने एक नई सांस्कृतिक परंपरा की नींव रखी।



30.75 करोड़ की अतिरिक्त लागत से बनेगा कालेज का नया तल

एनसीएल ने माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज के विस्तार के लिए किया एमओयू

सीधी (नि.प्र.)



कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली परिक्षेत्र में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक क्षमता निर्माण को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थापित किए जा रहे माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज भवन के विस्तार हेतु एनसीएल एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल के मध्य 15 अक्टूबर 2026 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

एनसीएल कर रहा 107 करोड़ से अधिक का सीएसआर व्यय

इस एमओयू के तहत 30.75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत से निर्माणाधीन माइनिंग कॉलेज में एक अतिरिक्त तल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही संस्थान के विकास में एनसीएल का कुल सीएसआर व्यय 107 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। सिंगरौली क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल के साथ प्रारंभिक एमओयू किया था। इसके तहत 76.56 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इस परियोजना पर 43.47 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। शेष 33 करोड़ से मूल परियोजना को मार्च 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

चितरंगी के ग्राम बर्दी में जन विश्वास शिविर आज

■ राज्यमंत्री राधा सिंह होंगी शामिल

सीधी (नि.प्र.)



मध्यप्रदेश शासन की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह दो दिवसीय प्रवास पर 15 एवं 16 अक्टूबर को सिंगरौली जिले में रहेंगी। अपने प्रवास के दौरान राज्यमंत्री 16 अक्टूबर को चितरंगी विकासखंड के ग्राम बर्दी में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में शामिल होंगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह 15 अक्टूबर को भोपाल से विमान द्वारा रीवा पहुंचेंगी। इसके बाद सड़क मार्ग से चितरंगी के लिए रवाना होंगी, जहां रात्रि विश्राम करेंगी। अगले दिन 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे चितरंगी से प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे ग्राम बर्दी पहुंचेंगी। यहां आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में शामिल होकर कार्यक्रम में सहभागिता करेंगी।

शिविर के बाद राज्यमंत्री शाम 4.30 बजे ग्राम पंचायत धरौली पहुंचेंगी। यहां वे स्वर्गीय गोविंद शुक्ला के निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। इसके पश्चात शाम 5.30 बजे चितरंगी लौटेंगी तथा शाम 7 बजे बैढ़न के लिए रवाना होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वे रात 8-30 बजे बैढ़न पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगी।

तुम आतंकवादी हो..., अमेरिका में मोहम्मद यूनुस का विरोध



नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश की पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी प्रवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। सोमवार को जब वह हवाई अड्डे पहुंचे, तो प्रवासियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और गंभीर आरोप लगाए।

कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आतंकवादी कहा और उन पर कुछ लोगों की जान लेने तथा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। मुख्य सलाहकार पद से हटने के बाद यूनुस की यह पहली विदेश यात्रा है।

इस बीच बांग्लादेश सरकार के सलाहकार जाहिद उर रहमान ने स्पष्ट किया है कि ढाका इस मामले में विरोध करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।

हवाई अड्डे पर तीखी नोकझोंक- सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब यूनुस कतर एयरवेज की उड़ान से दोहा होकर टर्मिनल 8 पहुंचे। जब उन्हें व्हीलचेयर पर बाहर लाया जा रहा था, तब भीड़ ने वापस जाओ के नारे लगाए और तीखे सवाल किए। एक प्रदर्शनकारी ने चिल्लाते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की हत्या की है और पूछा कि वह अमेरिका क्यों आए हैं।

प्रदर्शनकारियों ने यूनुस पर हजारों पुलिसकर्मियों की मौत का जिम्मेदार होने और करीब दो लाख लोगों की गिरफ्तारी कराने का भी आरोप लगाया। हंगामे को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत यूनुस और उनकी सहयोगी लामिया मोर्शेद को वापस हवाई अड्डे के अंदर पहुंचाया।

रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक बताया गया है, हालांकि यूनुस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कानून-व्यवस्था की नाकामी के आरोप- न्यूयॉर्क में दिखा यह आक्रोश मुख्य रूप से अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में फैली अशांति और हिंसा को लेकर है। आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि अंतरिम सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही।

अवामी लीग का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिंसा का निशाना बनाया गया। इसके साथ ही कई प्रमुख लोगों की हत्याओं और देश भर में फैली अशांति ने प्रशासन की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।अंतरिम सरकार के दौरान मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भी चिंताएं सामने आई। हिंदू समुदाय और उनके धर्मस्थलों पर हमलों, मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारियों और हिरासत में होने वाली मौतों को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने जवाबदेही की मांग की।

इसके अलावा जनवरी 2026 में जारी एक अध्यादेश के तहत 2024 के विद्रोह में शामिल लोगों के खिलाफ नियमित पुलिस जांच पर रोक लगा दी गई थी। पुलिसकर्मियों की मौत से जुड़े मामलों को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स) को भेज दिया गया, जिसे अपराध के मामलों को सामान्य कानूनी प्रक्रिया से भटकाने वाला कदम माना गया।

भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ाई तल्खीयूनुस के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों में भी भारी गिरावट आई। मार्च 2025 में चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर उनकी टिप्पणियों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ी, जिस पर भारत ने संयम बरतने की सलाह दी थी।इसके अलावा यूनुस और उनके ग्रामीण ग्रुप के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी उठ रही है। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे की यह घटना दर्शाती है कि बांग्लादेश के अशांत दौर का नेतृत्व करने वाले यूनुस को लेकर प्रवासी समुदाय के एक हिस्से में अभी भी गहरा असंतोष मौजूद है।

अमेरिका- जॉर्जिया में रोलर कोस्टर से गिरकर एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल



नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में स्थित प्रसिद्ध सिक्स फ्लैग्स ओवर जॉर्जिया अम्यूजमेंट पार्क में सोमवार को एक दर्दनाक रोलर कोस्टर हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए हैं।

11Alive के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही कॉब काउंटी पुलिस विभाग के जासूसों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, पुलिस और पार्क प्रशासन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि हादसा किस वजह से हुआ और किस रोलर कोस्टर पर हुआ।

गोलियथ कोस्टर से यात्रियों को बाहर निकाले जाने के फुटेज सामने आए हैं। अधिकारियों और सिक्स फ्लैग्स ने उस रोलर कोस्टर की पहचान नहीं बताई। बताया जा रहा है कि युवक की मौत रोलर कोस्टर से गिरने से हुई, वहीं इस दौरान चार अन्य लोग भी घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, सोमवार दोपहर सिक्स फ्लैग्स ओवर जॉर्जिया पार्क में एक रोलर कोस्टर से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हालांकि, कॉब काउंटी पुलिस विभाग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि हादसा किस वजह से हुआ और वह व्यक्ति कैसे गिरा।

जांच जारी...मामले की जांच जारी है, और %सिक्स फ्लैग्स% के प्रवक्ता ने कहा है कि पार्क प्रशासन स्थानीय अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहा है।

डोन लॉ फर्म के अनुसार, जॉर्जिया पार्क में यह कम से कम सातवीं मौत होगी। इस फर्म के काम के दायरे में एम्यूजमेंट पार्क में होने वाले हादसे भी शामिल हैं। फर्म के मुताबिक, पिछली मौतों में 2006 की एक घटना भी शामिल है, जिसमें गोलियथ कोस्टर पर एक व्यक्ति को शायद हार्ट अटैक आया था।

इस घटना पर दुख जताते हुए सिक्स फ्लैग्स ओवर जॉर्जिया ने कहा, आज हमारे पार्क में हुई घटना से हम बेहद दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं और हार्दिक शोक संतप्त परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ हैं।

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को भारत और विदेश में मिले 2225 करोड़ के नए ठेके



नई दिल्ली (एजेंसी)।कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने 2,225 करोड़ रुपये के ताजे ऑर्डर हासिल किए हैं, जिसमें भारत और विदेशी बाजारों में लगभग 2,031 करोड़ रुपये के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन, या टी एंड डी, कॉन्ट्रैक्ट आदि शामिल हैं। इसकी स्वीडिश सब्सिडियरी कंपनी, Linjemontage i Grästorp AB, ने स्वीडन में 130 केवी सबस्टेशन पर काम के लिए लगभग 194 करोड़ रुपये का ठेका अलग से हासिल किया है।

ऑर्डर जीतने से कंपनी के घोषित ऑर्डर फ्लो में अब तक ख्रङ्घ27 में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो मैनेजमेंट के अनुसार साल-दर-साल 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। इसलिए, कॉन्ट्रैक्ट का यह लेटेस्ट सेट सिर्फ बैकलॉग में एक नियमित जोड़ नहीं है, बल्कि टी एंड डी के केपीआईएल की ग्रोथ पाइपलाइन का प्रमुख चालक बने रहने का और प्रमाण है।

टी एंड डी पहले से ही केपीआईएल की सबसे बड़ी ऑर्डर-बुक वर्टिकल थी, जो 30 जून 2026 तक इसके समेकित ऑर्डर बुक के 66,607 करोड़ रुपये का 44 प्रतिशत हिस्सा है। हाल ही में घोषित 2,225 करोड़ रुपये के ऑर्डर उस जून-अंत बैकलॉग का लगभग 3.3 प्रतिशत के बराबर हैं।

इसके बिजनेस को भारत और साथ ही विदेशी बाजारों में ग्रिड एक्सपेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी निकासी और बिजली नेटवर्क की विश्वसनीयता पर उच्च खर्च से लाभान्वित हो रहा है।

स्वीडिश कॉन्ट्रैक्ट बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी श्वद्यद्यद्ग1द्बश्र क्क द्वारा पब्लिक खरीद प्रोसेस के जरिए दिया गया था। लगभग 200 मिलियन स्श्वद्य (190 करोड़ रुपये) की इस परियोजना में बोरलांगे में रेपबैकन में एक मौजूदा 130 केवी सबस्टेशन का रेनोवेशन और एक्सपेंशन शामिल है।मौजूदा स्टेशन परिसर के अंदर ही एक नया 130 द्यङ्क सबस्टेशन बनाएगी और उसे चालू सबस्टेशन से जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद ग्रिड की मजबूती और क्षमता को बढ़ाना है। श्वद्यद्यद्ग1द्बश्र ने बताया है कि आगे चलकर चार नई ओवरहेड लाइनें और एक 400 द्यङ्क बे भी इसी नए स्टेशन से जोड़ी जाएंगी, ताकि इसे के ट्रांसमिशन नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके।स्वीडिश सब्सिडियरी इस प्रोजेक्ट को टर्नकी मॉडल पर पूरा करेगी, जिसमें सिविल और फाउंडेशन वर्क, कंट्रोल बिल्डिंग, कंट्रोल इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही काम शुरू होने की उम्मीद है, और फाइनल इंस्पेक्शन 15 अक्टूबर 2029 को तय किया गया है। 2,924 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया मनीष मोहनोत ने कहा कि यह ऑर्डर कंपनी की एग्जीक्यूशन और इंजीनियरिंग क्षमताओं पर ग्राहक के भरोसे को दिखाता है।

हमारे लिए दुआ करो, 1 लाख करोड़ साम्राज्य के मालिक भारतीय अरबपति को AI ने डराया



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की IT कंपनी जोहो इस समय चर्चा में है। कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके अपने कर्मचारियों से माफी मांगी। दरअसल, एआई की वजह से इस बार जोहो अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट नहीं दे रही।

सैलरी में इजाफा क्यों नहीं किया जाएगा इसके पीछे का कारण भी श्रीधर वेम्बू ने अपनी पोस्ट में बताया है और साथ ही कहा है कि हमारे लिए दुआ करें।

1 लाख करोड़ से ज्यादा है जोहो की वैल्यूएशन- श्रीधर वेम्बू की जोहो शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है। इसकी अनुमानित वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। पिछले साल यह कंपनी अपने मैसेजिंग एप Arattai के कारण चर्चा में आई थी। कंपनी का यह प्रोडक्ट WhatsApp की ही तरह है।

इस मैसेजिंग एप के अलावा जोहो अपने क्लाइंट्स के लिए कई तरह के डिजिटल प्रोडक्टस भी बनाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्वाइंट, गूगल का जीमेल है, ठीक उसी प्रकार जोहो का जोहो शो है और जोहोमेल है।

भारत के कई सरकारी मंत्रालय भी इस कंपनी के जोहो मेल और जोहो शो जैसे सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, एआई की वजह से जोहो पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। यही कारण है कि जोहो अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट नहीं दे रही है।

फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने एक्स पर लिखा- सॉफ्टवेयर बिजनेस का भविष्य अनिश्चित है और AI की वजह से लागत बहुत बढ़ गई है। इसके दो मुख्य कारण हैं डेटा सेंटर के लिए जरूरी सर्वर की कीमतों में भारी (4 गुना) बढ़ोतरी और AI का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल, जिससे खर्च बहुत बढ़ गया है और हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इसके अलावा, जियोपॉलिटिकल हालात भी चुनौतीपूर्ण हैं। इन सबके चलते जोहोने अपने मार्केटिंग बजट में कटौती की है। और अपने कर्मचारियों को यह भी बता दिया है कि इस साल हम आम तौर पर दी जाने वाली सैलरी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। श्रीधर ने लिखा- ऐसा न कर पाने के लिए मैंने उनसे मांफी भी मांगी है।

हम बड़े पैमाने पर छंटनी से बचने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आम तौर पर सॉफ्टवेयर नौकरियों का भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। पिछले 18 महीनों से हमने कर्मचारियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।हमारे ज्यादातक कर्मचारी हालात को समझते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।

उन्होंने आगे कहा कि हम खुद को नए सिरे से ढालने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगले 3-5 साल यह तय करेंगे कि हमारी यह कोशिश कितनी कामयाब रही है। कृपया हमारे लिए दुआ करें।

यूपी की ये डेयरी कंपनी रोज बेचती है 11 लाख लीटर दूध, कर्ज में दबे बिजनेस को बनाया दुधारू गाय



कारोबार- ज्ञान डेयरी की कहानी साल 2007 में शुरू हुई। जय अग्रवाल और उनके भाई अनुज अग्रवाल पहले परिवार के तंबाकू कारोबार से जुड़े थे। लेकिन वे कुछ नया करना चाहते थे, जहां अपने फैसलों के दम पर कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। दोनों ने रियल एस्टेट में भी अवसर तलाशे, लेकिन बात नहीं बनी।

90 के दशक में यूपी में लोकप्रिय डेयरी कंपनी ज्ञान भारी वित्तीय संकट से गुजर रही थी और उसके मालिक साझेदार की तलाश में थे। जय ने अपने परिवार को इस बिजनेस से जुड़ने की इच्छा बताई और डेयरी बिजनेस में हाथ डालने का निर्णय लिया। ऐसे बिजनेस में उतरने का साहस दिखाया, जिसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान, अनुभव या विशेषज्ञता नहीं थी।

नई दिल्ली (एजेंसी)। आपने अमूल का दूध तो खूब पिया होगा, लेकिन क्या आप उत्तरप्रदेश की उस डेयरी कंपनी के बारे में जानते हैं, जिसने बड़े ब्रांड्स के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। इसकी शुरुआत दो प्रोडक्ट्स से हुई थी, लेकिन आज कंपनी दूध से लेकर घी, दही, पनीर और छाछ तक बेचती है। खास बात यह है कि इस सफर में कंपनी को किसानों का भरोसा जीतने से लेकर दूध की सप्लाई का मजबूत नेटवर्क तैयार करने तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की ज्ञान डेयरी की, जिसे जय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने आगे बढ़ाया।

बंद डेयरी प्लांट से शुरू हुआ

जर्मनी में 16 साल की लड़की के साथ रोबोट ने की छेड़छाड़; पुलिस ने जब्त की मशीन



1.2 मीटर ऊंचा रोबोट कथित तौर पर उसके पीछे से आया। बताया जा रहा है कि इस घटना को फिल्माया गया और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया गया।

नई दिल्ली (एजेंसी)। जर्मनी के कोलोन शहर में एक फास्ट-फूड रेस्टोरेंट के बाहर एक रोबोट ने कथित तौर पर 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना को कथित तौर पर फिल्माया गया और सोशल मीडिया पर लाइव-स्ट्रीम किया गया।

पुलिस ने इस मामले में दो किशोरों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या लड़की को परेशान करने के लिए मशीन को जानबूझकर कंट्रोल किया गया था।

रोबोट ने की लड़की के साथ छेड़छाड़-डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना रविवार रात करीब 11ः45 बजे सेंट्रल कोलोन की होहेनजोलर्नरिंग पर हुई। लड़की अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, तभी लाल और सुनहरे रंग का करीब छुआ और उसे धक्का दिया। पुलिस को शक है कि रोबोट के 16 साल के मालिक (जो वेग्बर्ग का रहने वाला है) और उसके 19 साल के साथी ने घटना को फिल्माया और घटना के दौरान कमेंट्री भी की।

दो किशोरों के फोन भी पुलिस ने किए जब्त - रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्धों की फॉक्सवैगन सेडान कार की डिक्की में रोबोट पाया। इसके बाद अधिकारियों ने जांच के तहत मशीन और किशोरों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए।

पुलिस ने एक बयान में कहा, अधिकारियों ने संदिग्धों का रोबोट और दो मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यौन उत्पीड़न के शक की जांच कर रहा है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना के समय रोबोट कैसे काम कर रहा था और क्या उसे दूर से कंट्रोल किया जा रहा था।

मेरे राष्ट्रपति.. माफ कीजिए, मेरे पति, जब ब्रीफिंग के दौरान लड़खड़ाई ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी की जुबान



नई दिल्ली (एजेंसी)। डोनल्ड ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी केटी जकारिया की पहली प्रेस ब्रीफिंग कुछ अजीब ढंग से हुई। मंगलवार को उन्होंने अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग की। ये तब हुआ, जब वह चार बच्चों की परवरिश और अपने नौकरी के बीच तालमेल बिठाने से जुड़े सवाल पर अपने पति और राष्ट्रपति में कन्फ्यूज हो गई। इस दौरान उनका अपने ट्रंप को पति कह देना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मेरे पति के बजाय कह गई मेरे राष्ट्रपति-ब्रीफिंग के दौरान तब अजीब पल आया जब उन्होंने गलती से मेरे पति कहने के बजाय मेरे राष्ट्रपति कह दिया।

केटी से सवाल किया गया था कि वह नौकरी और चार बच्चों की परवरिश के बीच कैसे तालमेल बिठाएगी। इस सवाल का जवाब देते हुए केटी ने कहा, तो मेरे राष्ट्रपति...माफ कीजिए, मेरे पति... यह तो मजेदार बात हो गई।

दरअसल केटी के पति और बच्चे कैलिफोर्निया में रहते हैं। उनके चार बच्चे हैं। ऐसे में उनसे सवाल किया गया था कि वह वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी रहते हुए बच्चों और पति को कैसे समय देंगी। इस पर उन्होंने कहा कि परिवार जल्दी दी राजधानी में रहने के लिए आ जाएगा। उनकी यह ब्रीफिंग सिर्फ 14 मिनट तक चली।

कौन है केटी के पति- केटी के पति टायलर जकारिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिल्म प्रोड्यूसर और 2521 एंटरटेनमेंट में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। दोनों 2016 से साथ है। ब्रीफिंग के दौरान, केटी ने बताया कि काम पर लौटने से पहले वह 2014 से 2020 तक घर पर अपने बच्चों के साथ रही थीं।

फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले श्रीलंकाई नागरिक की मौत की सजा रद, सऊदी अरब ने पलटा फैसला



नई दिल्ली (एजेंसी)। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के किसी पोस्ट पर टिप्पणी करने के लिए एक प्रवासी कर्मचारी को सुनाई गई मौत की सजा को रद कर दिया है। ये जानकारी कोलंबों के उप-विदेश मंत्री अरुण हेमाचंद्र ने दी है। मामला सऊदी अरब की अपील कोर्ट का है, जहां पर 27 साल के अनोझन शिवरासा को मौत की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने सितंबर में उन्हें अपनी टिप्पणी में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा का दोषी ठहराया था।

इस मामले के सामने आते ही श्रीलंका में हलचल मच गई। इसके साथ ही वहां सजा के खिलाफ माफी की कोशिश तेज हो गई।

उप-विदेश मंत्री ने कानूनी टीमों का किया शुक्रिया अदा- कोलंबों के उप-विदेश मंत्री अरुण ने फेसबुक के जरिए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद कर दी है। तनाव के बाद इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उन्होंने दोनों देश के अधिकारियों और कानूनी टीमों को धन्यवाद दिया है।

पीड़ित अनोझन के इस मामले की शुरुआत एक वीडियो पोस्ट के जरिए हुई थी। जिसमें एक यूजर हिंदू देवता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है जवाब में अनोझन पर भी गलत टिप्पणी का आरोप लगा। एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। यहीं से शुरू हुए हिंदू-मुस्लिम विवाद के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

स्क्रीनशॉट पर हुई कार्रवाई- हालांकि बाद में अनोझन ने टिप्पणी तुरंत हटा दी लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट सऊदी के अधिकारियों तक पहुंच गया। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

श्रीलंका के सांसद ने निभाई सराहनीय भूमिका

श्रीलंका के सांसद फाइजर मुस्तफा इस मामले में अनोझन के लिए सऊदी अरब से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने समाचार वेबसाइट बीबीसी को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ये भी बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रहे हैं।

बांग्लादेश ने की भारत से एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाने की मांग, कारोबार को आसान करना चाहता है पड़ोसी! क्या है भारत का स्टैंड?



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशों के तहत 8 और 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में व्यापार संबंधी बातचीत हुई। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए ऊंचे इंपोर्ट ड्यूटी, कपास के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ व्यापार के नियमों का मुद्दा उठाया। वहीं, बांग्लादेश ने भारत से अपने उत्पादों की पहुंच आसान बनाने, जूट उत्पादों और PET फिल्म पर एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने और सीमा पर माल की आवाजाही बेहतर करने की मांग की।

दोनों देशों के बीच ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की यह बैठक लंबे अंतराल के बाद हुई है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस व्यापार वार्ता को पॉजिटिव बताया गया है। इससे दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों के बीच प्रस्तावित बैठक की तैयारी में मदद मिलने की उम्मीद है।

बातचीत के दौरान भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में भारतीय कपास के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया। इसके अलावा, भारतीय फल, चावल, लोहा और इस्पात जैसे उत्पादों पर लगाए गए ऊंचे आयात शुल्क पर भी चिंता जताई गई। भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भूमि सीमा चौकियों के जरिए होने वाले व्यापार में बांग्लादेश की ओर से लागू पॉजिटिव लिस्ट व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया।

इसके उलट, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के साथ बांग्लादेश का व्यापार नेगेटिव लिस्ट के आधार पर होता है। इसमें कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं को छोड़कर अन्य उत्पादों के व्यापार की अनुमति होती है। भारत लंबे समय से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भी नेगेटिव लिस्ट व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहा है, ताकि दोनों पक्षों के कारोबारियों को समान अवसर मिल सकें।भारत ने अंतरिम सरकार के कार्यकाल में बंद किए गए सीमा हाट यानी सीमावर्ती बाजारों, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और लैंड कस्टम्स पोस्ट को दोबारा शुरू करने का मुद्दा भी उठाया।

एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने की मांगबांग्लादेश ने भारतीय भूमि बंदरगाहों के जरिए अपने उत्पादों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों का रिव्यू करने की मांग की। उसने जूट उत्पादों और पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म पर लागू एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने का मुद्दा भी उठाया।÷एंटी-डंपिंग ड्यूटी किसी दूसरे देश से आयात होने वाले उत्पादों पर तब लगाया जा सकता है, जब वे निर्धारित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बेचे जा रहे हों और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने की स्थिति हो।

संक्षिप्त समाचार

सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों में जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें : डॉ. यादव



भोपाल नगर संवाददाता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के बारह जिलों क्रमश : आलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, हरदा और शाजापुर में सामान्य से कम वर्षा हुई हैं। आनेवाले दिनों में इन जिलों में जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना होगा। सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल को दी जाएं, इसके साथ ही किसानों को कम पानी वाली फसलें लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएं। सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों में इस स्थिति से निपटने के लिए वातावरण निर्मित करने में जल उपभोक्ता समितियां भी अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश प्रदेश में मानसून और वर्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जल संसाधन तुलसी सिलावट, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के प्रमुख बांधों, जलाशयों में जलभराव की स्थिति, कम वर्षा वाले जिलों और उनके जल स्त्रोतों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही नदियों में जलप्रवाह, भू-जलस्तर, मृदा में नमी जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से जलगंगा अभियान के अंतर्गत गतिविधियां आरंभ करने के संबंध में भी निर्देश दिए। बैठक में राजस्व, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने श्रमिक-कर्मचारी संगठनों से किया संवाद



भोपाल नगर संवाददाता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी वर्गों को मूलभूत सुविधाएं तथा आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी के हित के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सभी विभाग, प्रदेश में सक्रिय उनसे संबंधित श्रमिक संघों और कर्मचारी संगठनों से सतत् संवाद में रहें। इससे उनकी कठिनाईयों का समय रहते समाधान संभव होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार विभिन्न कर्मचारी संगठनों और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से मंत्रालय में चर्चा के दौरान व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को भी तत्परता से हल किया जाएगा। बैठक में उपमुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा तथा राजेन्द्र शुक्ल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल तथा मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय मजदूर संघ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

मंत्री सारंग ने की तैयारियों की समीक्षा

भारतीय सेना दिवस-2027 का भोपाल में होगा राष्ट्रीय समारोह

भोपाल (नगर संवाददाता)



भोपाल। मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार भोपाल में भारतीय सेना के राष्ट्रीय स्तर का गौरवशाली आयोजन होने जा रहा है, जो प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि और गर्व का अवसर होगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह समारोह देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को करीब से जानने का अवसर प्रदान करेगा।

इसके साथ ही, नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, सैन्य सेवाओं के प्रति सम्मान और देश की सुरक्षा के प्रति जागरूकता का भाव सुदृढ़ करेगा। आगामी 15 जनवरी 2027 को भोपाल में आयोजित होने वाले भारतीय सेना दिवस के राष्ट्रीय समारोह को लेकर गुरुवार को मंत्री सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में उच्च स्तरीय बैठक ली।

बैठक में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, खेल और युवा कल्याण विभाग, संस्कृति सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय सैन्य आयोजनों को दिल्ली से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय सेना ने भोपाल में सेना दिवस समारोह आयोजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

इस आयोजन की मुख्य थीम 'आपकी सेना-आपके पास' रखी गई है, जो भारतीय सेना और आम नागरिकों के बीच आत्मीय जुड़ाव को और मजबूत करेगी। सेना दिवस-2027 के अवसर पर भोपाल के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर मुख्य परेड के साथ अनेक भव्य एवं रोमांचक कार्यक्रम होंगे।

बीएचईएल स्थित कालीबाड़ी मार्ग में मुख्य आर्मी-डे परेड आयोजित होगी, जिसमें भारतीय सेना के अनुशासित दस्तों और सैन्य सामर्थ्य का भव्य प्रदर्शन होगा। टीटी नगर स्टेडियम, भोपाल में शौर्य संध्या 'रणहुंकार' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के साथ मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं जनजातीय विरासत को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

रबी फसलों के बीज का पर्याप्त भण्डारण

भोपाल (नगर संवाददाता)

भोपाल। किसानों को आगामी रबी मौसम के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज का पर्याप्त भण्डारण उपलब्ध है। जिलों में शासकीय एवं अन्य अधिकृत संस्थाओं के पास उपलब्ध है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिलों में बीज की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा की जा रही है। किसानों की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार बीज की पर्याप्त उपलब्धता है।

किसानों से आग्रह है कि वे अधिकृत विक्रय केन्द्रों एवं संबंधित सहकारी संस्थाओं से प्रमाणित बीज क्रय कर सकते हैं। बीज खरीदते समय टैग, बिल एवं बीज की वैधता जांच कर लें। अनियमितता या निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बीज विक्रय होने पर संबंधित जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दें। जिलों में मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में 91452 क्विंटल, शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में 12403, बीज संघ में 652739, राष्ट्रीय बीज निगम में 255718, अन्य संस्थाओं में 190839 क्विंटल इस प्रकार संस्थागत में 1203191 क्विंटल एवं निजी बीज संस्थाओं में 2548843 क्विंटल उपलब्ध है।

स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती देवी का स्मरण

भोपाल नगर संवाददाता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती देवी 'दुर्गा भाभी' की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दुर्गावती देवी जी का साहस, त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय एवं प्रेरणादायी रहेगा।

कमला नगर पुलिस की कार्रवाई, फरार वारंटी सूरज शूटर उर्फ छिद्दा विश्वकर्मा गिरफ्तार

भोपाल, 16 अक्टूबर 2026। भोपाल की कमला नगर पुलिस ने न्यायालयीन वारंटों की तामीली के लिए कार्रवाई करते हुए फरार वारंटी सूरज शूटर उर्फ छिद्दा विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को शबरी नगर स्थित एबीएम पार्क/अनिल डेयरी के पास से गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध विभिन्न मामलों में 5 स्थायी वारंट और 1 गिरफ्तारी वारंट लंबित थे। ये वारंट आर्म्स एक्ट, मारपीट एवं अन्य धाराओं से संबंधित मामलों में जारी किए गए थे। लंबे समय से लंबित वारंटों की तामीली के लिए थाना कमला नगर पुलिस ने कार्रवाई की। यह कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक निरूपा पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई। टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा न्यायालयीन वारंटों की तामीली की प्रक्रिया पूरी की। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य लंबित न्यायालयीन वारंटों का निष्पादन करना और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है।

गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पांचवें संस्करण का हुआ शुभारंभ

ऑल सीजन टेंट सिटी के साथ रोमांचक साहसिक गतिविधियों का मिलेगा आनंद

भोपाल (नगर संवाददाता)

भोपाल। ऑल सीजन टेंट सिटी के साथ जल, नभ और थल पर आधारित साहसिक गतिविधियों का प्रमुख आकर्षक गंतव्य गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पांचवें संस्करण का मंदसौर जिले के गांधीसागर जलाशय के सुरम्य बैकवाटर पर शुभारंभ हुआ। एमपी टूरिज्म बोर्ड और लह्लूजी एंड सन्स एवं इवोक कैंपिंग के सहयोग से आयोजित यह रिट्रीट पर्यटकों को चंबल के शांत जल विस्तार और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रोमांच और सुकून का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। रिट्रीट में पर्यटक हाई रोप, ज़िप्लाइन, एटीवी राइड, साइकलिंग, डुओ साइकिल, एयरगन शूटिंग और पैरामोटरिंग जैसी साहसिक और रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। पर्यटक स्पीड बोट, जेट स्कीइंग, बनाना बोट, ड्रैगन बोट और कयाकिंग का भी रोमांच ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त जंगल सफारी, नाइट वॉक, स्टार गेज़िंग, बोट सफारी, बोट स्पा, योग एवं वेलनेस सत्र तथा इनडोर खेलों की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। गरोठ विधायक चंदर सिंह सिसोदिया और कलेक्टर श्री दिव्यांक सिंह ने रिट्रीट का औपचारिक शुभारंभ किया।

स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन : रिट्रीट के माध्यम से पर्यटकों को मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कलाओं, पारंपरिक जीवनशैली और स्थानीय व्यंजनों से परिचित कराने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2023 में शुरू हुआ गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट अपने पांचवें संस्करण के साथ क्षेत्र में प्रकृति-आधारित एवं साहसिक पर्यटन को नई दिशा दे रहा है।

गांधीसागर की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से आतिथ्य, परिवहन, खानपान और स्थानीय उत्पादों से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

भोपाल में 4 से 7 दिसंबर तक होगा इज्तिमा संभागायुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा

भोपाल (नगर संवाददाता)

भोपाल। राजधानी भोपाल में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला पारंपरिक इज्तिमा इस वर्ष 04 दिसंबर से 07 दिसंबर 2026 तक ईटखेड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

इसी सिलसिले में संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में संभाग आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में इज्तिमा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं (जमातों) के लिए नागरिक सुविधाओं, सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (IG) शैलेन्द्र सिंह चौहान, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के साथ-साथ इज्तिमा समिति के पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।



प्रशासन द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश

सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा और सुविधा : संभागायुक्त शर्मा ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने कार्यों को समय-सीमा में पूरा करें। इज्तिमा स्थल पर आने वाली जमातों की सुरक्षा और उन्हें बेहतर सुविधाएं देना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

पुख्ता सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट : आईजी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि इज्तिमा स्थल पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम हों और ट्रैफिक पुलिस द्वारा सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी को असुविधा न हो।

हेल्प डेस्क की स्थापना : अन्य जिलों और राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर विशेष हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे।

विद्युत सुरक्षा और वॉलिंटियर्स : इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के कार्यों की सुरक्षा मानकों के तहत पूर्व और पश्चात जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, वालंटियर्स की सूची तैयार कर उन्हें स्थल की व्यवस्थाओं से अवगत कराया जाएगा ताकि वे समय पर जमातों की मदद कर सकें।

चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा : आपातकालीन स्थितियों में रिस्पॉन्स टाइम को न्यूनतम रखने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने को कहा गया है। इसके अलावा, फूड सेफ्टी अधिकारियों को खाद्य पदार्थों और पेयजल की गुणवत्ता की निरंतर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

मिनट-टू-मिनट एक्शन प्लान : संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग इज्तिमा स्थल के लिए एक मिनट-टू-मिनट एक्शन प्लान तैयार करें और उसी के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली तय करें, ताकि यह बड़ा आयोजन पूरी तरह सुरक्षित और सफल हो सके।



गरबा केवल नृत्य नहीं, माँ दुर्गा की आराधना और आस्था का उत्सव : किशन सूर्यवंशी

भोपाल (नगर संवाददाता)

भोपाल। जन कल्याण हिंदू उत्सव समिति द्वारा शहर में भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने माँ दुर्गा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गरबा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा, गरबा केवल नृत्य का माध्यम नहीं, बल्कि माँ दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति और मन की आराधना का प्रतीक है। यह महोत्सव हमारी सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक एकता को सशक्त बनाने के साथ ही समाज में उत्साह, उमंग और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस अवसर पर आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं और युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में सज-धजकर माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होकर गरबा किया। पूरे आयोजन ने धार्मिक उल्लास के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और समृद्ध परंपराओं की एक सुंदर झलक प्रस्तुत की।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इनमें मुख्य रूप से पार्षद राजमनी उईके, लीलेन्द्र सिंह मारण, जीवन मारण, जय सिंह मारणा, वैभव सिंह सिसोदिया और गोविन्द कहारे सहित कई अन्य गणमान्यजन शामिल हुए।

भोपाल मंडल : छह माह में 588 रेल कोचों का हुआ ओवरहॉलिंग, सुरक्षित रेल सफर को मिलेगी गति



भोपाल। पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुचारु और आरामदायक रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में भोपाल स्थित कोचिंग रिपेयर वर्कशॉप (CRWS) ने चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह महीनों में कुल 588 कोचों का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग (POH) पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अकेले सितंबर माह में ही 115 कोचों का अनुरक्षण (मेंटेनेंस) किया गया। जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य कारखाना प्रबंधक के मार्गदर्शन में वर्कशॉप में निर्धारित मानकों और उच्च गुणवत्ता के साथ कोचों का ओवरहॉलिंग कार्य किया जा रहा है।

ओवरहॉलिंग के दौरान इन पुर्जों की होती है सघन जांच

- **सुरक्षा उपकरण :** एयर ब्रेक प्रणाली, बफर और अंडरगियर की विस्तृत मरम्मत।
- **बोगी और ट्रॉली :** ट्रॉली और बोगी के महत्वपूर्ण पुर्जों का गहन परीक्षण और मेंटेनेंस।
- **पहिये और धुरियां :** कोच के पहियों और धुरियों (A&les) का सूक्ष्म निरीक्षण, ताकि यात्रा के दौरान किसी तकनीकी खामी की गुंजाइश न रहे।

भोपाल के न्यू मार्केट अग्निकांड का मामला

दुकान संचालक पर एफआईआर, हॉकर्स शिफ्टिंग और फायर सेफ्टी की जांच तेज

भोपाल (नगर संवाददाता)



भोपाल। भोपाल के न्यू मार्केट में 8 अक्टूबर को हुए भीषण अग्निकांड के मामले में पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टीटी नगर पुलिस ने बालाजी छोला-भटूरा दुकान के संचालक दीप उर्फ दीपू अग्रवाल के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि दुकान में जल रही भट्टी के पास रखे कपड़ों में आग भड़की थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की कई दुकानों व रेहड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान है।

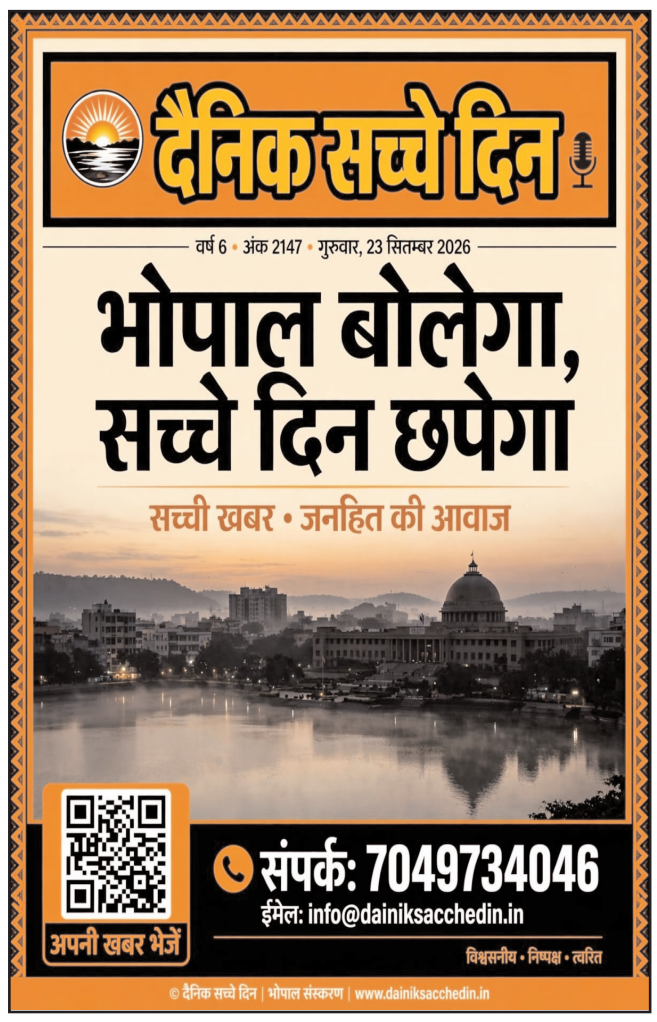
घटना के बाद आम्रपाली रेस्टोरेंट के संचालक पवन अग्रवाल की शिकायत और पुलिस जांच के आधार पर टीटी नगर पुलिस ने दुकान संचालक पर केस दर्ज किया है, जिसमें आम्रपाली रेस्टोरेंट, विजय स्टोर, एक मोबाइल दुकान और 12 से अधिक रेहड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा था। हादसे के बाद नगर निगम ने न्यू मार्केट को व्यवस्थित करने के लिए हॉकर्स को टीटी नगर स्टेडियम के पास हाट बाजार में शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अतिक्रमण अधिकारी शैलेंद्र सिंह भदौरिया के अनुसार, निर्देशों का पालन न करने पर सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत

भोपाल। भोपाल के ऐशबाग इलाके में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां बरखेड़ी रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 60 वर्षीय बुजुर्ग कमल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पहले ड्राइवर के रूप में कार्य करते थे, लेकिन आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्होंने कुछ समय पहले काम करना छोड़ दिया था और वे अधिकांश समय घर पर ही रहते थे।

गुरुवार सुबह वे अपनी रोजचर्या के तहत टहलने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान ट्रैक पार करते वक्त यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है और मामले में आगे की कानूनी जांच जारी है।





स्वात्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक , प्रकाशक **साहबजादा अब्दुल रशीद खान** द्वारा आर.के. एण्ड प्रिंटर्स 7 नीम वाली सड़क जिंसी जहांगीराबाद भोपाल म.प्र.482008 से मुद्रित तथा 424, मेहंदी वालीगली, तलैया भोपाल म.प्र. 462001 से प्रकाशित।
सम्पादक- अज़रा बैगम (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल न्यायालय रहेगा।) RNI No. MPHIN/2021/82412